आज का विचार
जीवन से भागने की कोशिश मत करो। जीवन तुम्हें जो देगा, वही तुम्हें बड़ा बनाएगा।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

8

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 वर्ष 24, अंक 2, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया डीआरडीओ जल्द ही बना लेगा स्वदेशी 'सुदर्शन चक्र'

रक्षा मंत्री बोले- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ के हथियारों की रही अहम भूमिका

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि डीआरडीओ अगले दशक में देश की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए हमारे जरूरी ठिकानों को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने के लिए तैयार है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई युद्ध में एयर डिफेंस की अहमियत देखी। मुझे भरोसा है कि डीआरडीओ जल्द ही इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल से काम करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि डीआरडीओ जल्द ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 की तर्ज पर स्वदेशी 'सुदर्शन चक्र' बना लेगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के 68वें स्थापना दिवस के मौके पर नई दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा करने के दौरान रक्षा मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की हथियार प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संगठन की व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता का सबूत है। सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करके भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान हथियारों ने बिना किसी रुकावट के काम किया, जिससे सैनिकों का हौसला बढ़ा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में स्वदेशी सुदर्शन चक्र बनाने की घोषणा की थी, जिसमें डीआरडीओ अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत डीआरडीओ अगले दशक में हवाई सुरक्षा

पक्का करने के लिए हमारे जरूरी ठिकानों को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने के लिए तैयार है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के दौरान एयर डिफेंस की अहमियत देखी। मुझे भरोसा है कि डीआरडीओ जल्द ही इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल से काम करेगा।

राजनाथ सिंह ने प्राइवेट सेक्टर के साथ डीआरडीओ के सहयोग को मानते हुए कहा कि रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स के साथ बढ़ते जुड़ाव से एक तालमेल वाला रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बना है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने लगातार अपने काम करने के तरीकों में सुधार किया है। खरीद से लेकर परियोजना प्रबंधन तक, उद्योग जुड़ाव से लेकर स्टार्ट अप और लघु उद्योगों के साथ मिलकर काम करने तक, काम को आसान, तेज और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश दिख रही है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ से कहा कि वह तेजी से बदलते तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ता रहे और बदलते समय के हिसाब से उत्पाद लाता रहे।

उन्होंने डीप टेक और नेक्स्ट-जेनरेशन टेक्नोलॉजी की दिशा में डीआरडीओ की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि इस कोशिश में तरक्की से न सिर्फ. देश की काबिलियत बढ़ेगी, बल्कि डिफेंस इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का जमाना सिर्फ साइंस का नहीं है, बल्कि लगातार डेवलपमेंट और लगातार सीखने का है। इस बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी स्कैनिंग, काबिलियत का अंदाजा और भविष्य की तैयारी अब सिर्फ शब्द नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया हर दिन बदल रही है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नए युद्ध के तरीके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कल का ज्ञान बेकार हो रहा है। हमें कभी यह नहीं मान लेना चाहिए कि सीखने का प्रोसेस खत्म हो गया है। हमें सीखते रहना चाहिए और खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी के लिए रास्ता बन सके।

प्रदेश को विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की ओर अग्रसर डबल इंजन सरकार: नायब सिंह सैनी

नव वर्ष में सरकार अंत्योदय के तीन मूल मंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर करेगी कार्य

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। नव वर्ष में इस अभियान को नई गति देने का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार अंत्योदय उत्थान के साथ साथ इस नए वर्ष में अंत्योदय के तीन मूल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण करने का है। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के तहत अब तक 8 लाख महिलाओं को दो किस्तों में 250 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से आग्रह किया है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाएं पंजीकरण कर इस योजना के साथ जुड़े और इसका लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का दूसरा लक्ष्य युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करना है। सरकार ने 2026 के लिए ड्रिवन रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में हरियाणा एआई मिशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन केंद्रो में युवा भविष्य की तकनीक जैसे एआई, कुशल रोबोटिक में निपुण बन सकेंगे। सरकार इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज ही पुलिस विभाग के 5500 कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रकृति के अनुकूल खेती करने का तीसरा लक्ष्य रखा है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने पर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत एक लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को तेजी से पूर्ण करवाना भी सरकार का लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट बेहतर कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित करेगा, जिससे दिल्ली के चारों और एनसीआर क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे ही कई नई परियोजनाओं को नए वर्ष में गति देने का काम करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के समुचित विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने कुंजपुरा , मतलौडा और शहजादपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया है।

महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने और दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है, इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल (ल्ध्ंल्ल उंस्र्इ') पर अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों -बेटियों के लिए शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है। अब इस योजना को सामाजिक विकास के साथ जोड़ा जाएगा और इसके लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को जोड़ा गया है। इसके तहत, वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा, बशर्ते कि उन माताओं ने विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बच्चों की शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया है।

भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सकारात्मक बदलाव का बड़ा अवसर: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आज पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। यह हमारे सीखने, काम करने, आधुनिक सेवाओं तक पहुंच और मानवता की बड़ी चुनौतियों से निपटने के तरीकों को तेजी से बदल रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का बड़ा अवसर है।

राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को भविष्य की एआई प्रवीणता से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जागरूकता अभियान ह्यस्किल द नेशन चैलेंजह्न का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल माध्यम से ओडिशा के रायरांगपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन भी किया।

इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति ने कहा कि 'भारत का दृष्टिकोण हमेशा से यह रहा है कि तकनीक लोगों को सशक्त बनाए, समावेशी हो और सभी के लिए अवसर पैदा करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी खाइयों को पाटने के लिए किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसके लाभ हर वर्ग, हर उम्र और खासकर हाशिये पर खड़े समुदायों तक पहुंचे।' उन्होंने यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की कि छात्र खुद को संभावनाओं और अवसरों से भरे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने छात्रों से आग्रह किया कि वे यह याद रखें कि तकनीक, ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा, समस्याओं के समाधान और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने उन संसद सदस्यों की भी सराहना की जिन्होंने एआई लर्निंग मॉड्यूल पूरे किए हैं और कहा कि उभरती तकनीकों को स्वयं सीखकर उन्होंने नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

स्किल द नेशन चैलेंज के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह पहल बड़े पैमाने पर एआई लर्निंग और इनोवेशन में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी और लाखों शिक्षार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करेगी। उन्होंने एआई प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले सांसदों और बच्चों को बधाई भी दी।

भारत-पाकिस्तान ने कैदियों, मछुआरों और परमाणु ठिकानों की सूची की साझा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यमों से गुरुवार को साल 2008 में हुए कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने अपनी हिरासत में बंद 391 नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की सूची पाकिस्तान के साथ साझा की है। यह नागरिक या तो पाकिस्तानी हैं या इन्हें पाकिस्तानी माना जाता है। साथ ही पाकिस्तान ने भी 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की सूची भारत को

सौंपी है। यह नागरिक या तो भारतीय हैं या इन्हें भारतीय माना जाता है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हमले के निषेध पर सहमति वाले समझौते के तहत आज परमाणु ठिकानों की सूचियों का भी आदान-प्रदान किया। इसके तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को एक-दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची साझा करते हैं। इस बार दोनों देशों के बीच सूचियों का यह लगातार 35वां आदान-प्रदान है। पहली बार यह प्रक्रिया 1 जनवरी 1992 को शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से अपनी हिरासत में मौजूद भारतीय नागरिक कैदियों, मछुआरों, उनकी नौकाओं और लापता भारतीय कर्मियों की जल्द रिहाई और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। भारत ने विशेष रूप से 167 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई में तेजी लाने का अनुरोध किया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। इसके अलावा, पाकिस्तान से 35 ऐसे नागरिक कैदियों और मछुआरों को तत्काल राजनयिक पहुंच देने को कहा गया है, जिन्हें भारतीय माना जाता है लेकिन अब तक राजनयिक पहुंच नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जाए, जब तक उनकी रिहाई और प्रत्यावर्तन न हो। भारत सरकार के सतत प्रयासों से साल 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को वापस लाया गया है। इनमें से 2023 से अब तक 500 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक कैदी रिहा किए गए हैं।

दो साल में रेलवे कुछ सेक्टरों पर प्रतीक्षा सूची को पूरी तरह खत्म करेगी: वैष्णव

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि बीते कुछ वर्षों से रेलवे नेटवर्क के क्षमता निर्माण कार्य इस स्तर पर पहुंच गये हैं कि अब गाड़ियों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जाएं। उन्होंने कहा कि दो साल में कुछ सेक्टरों की गाड़ियों की प्रतीक्षा सूची मुक्त हो जाने की आशा है।

वैष्णव ने यहां रेल भवन में संवाददाताओं से मुलाकात में कहा कि बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप रेलवे नेटवर्क के विस्तार एवं क्षमता वृद्धि की दिशा में बहुत काम हुआ है। हमारा मानना है कि जितनी मांग है, उसे क्षमता विस्तार किये बिना पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए बीते 11 साल में करीब 35 हजार किलोमीटर नयी पटरियां बिछायीं गयीं हैं। बीते साल करीब सात हजार किलोमीटर पटरियों को बदला गया है। लोकोमोटिव्स का उत्पादन बढ़ा है। 11 साल में करीब 42 हजार नये कोच बनाये गये हैं। जिन शहरों से गाड़ियां बन कर चलतीं हैं और जिन शहरों में गाड़ियां समाप्त होतीं हैं, उनमें स्टेशनों की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। संरक्षा के नये उपाय एवं नई तकनीक क्रियान्वित की जा रहीं हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्युतीकृत मार्गों में ओवर हेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) तारों की क्षमता एवं विद्युत पारेषण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 1960 के फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित ओएचई प्रणाली को 2७25 किलोवाट प्रणाली में बदला जा रहा है और जिन लाइनों का पहली बार विद्युतीकरण किया जा रहा है, वहां पर सीधे इसी प्रणाली को लगाया जा रहा है। इससे तेजगति वाली गाड़ियां एवं एक सेक्शन पर कई गाड़ियां एकसाथ चलाना संभव होगा।

उन्होंने कहा कि अब एक ऐसी स्थिति आने वाली है जब हम एक-एक सेक्टर चुन कर उसे मांग के आधार पर सीटें दे सकें। इस प्रकार से उन सेक्टरों में प्रतीक्षा सूची को शून्य या समाप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार से एक से दो साल में ऐसा समय आना चाहिए जब कुछ सेक्टरों पर गाड़ियों में मांग के आधार पर सीटें उपलब्ध करायीं जा सकेंगी और इस प्रकार से वहां प्रतीक्षा सूची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

शेखावत ने छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक सिरपुर के पुरातात्विक स्थलों का किया निरीक्षण

एजेंसी (हि.स.)
रायपुर

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला अंतर्गत ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल सिरपुर का दौरा किया। इस अवसर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी उनके साथ रहे। इससे पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री शेखावत का सिरपुर हेलीपैड पर सांसद महासमुंद रूपकुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक प्रभास कुमार और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री शेखावत ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल सिरपुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने लक्ष्मण देवालय, आनंद प्रभु कुटी विहार, तीवरदेव विहार, सुरंग टीला और स्थानीय हाट बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने सिरपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिरपुर भारत की प्राचीन धरोहर का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की आवश्यकता है।

उन्होंने संरक्षण और संवर्धन कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरातात्विक स्थलों की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाए। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर सड़क, साइन बोर्ड, सूचना केंद्र, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। आनंद प्रभु कुटी विहार, सुरंग टीला, तिवरदेव विहार, लक्ष्मण देवालय स्थानीय हाट बाजार का भी

निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सिरपुर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि यहां आकर गौरव की अनुभूति हो रही है। सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का प्रयास जारी है। यहां की ऐतिहासिक, पुरातत्विक और आध्यात्मिक नगरी हमारे समृद्ध संस्कृति और परम्परा का प्रतीक है। इसके संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विहारों और मंदिरों के अवशेषों की वर्तमान स्थिति को सहजने और संरक्षित करने पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने गंधेश्वर मंदिर पहुंचकर गंधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर देश के समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री, धर्मस्व और पर्यटन मंत्री के साथ सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, राज्य बीज निगम अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ विमल चोपडा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम ठाकुर, जनपद अध्यक्ष दिशा दीवान, उपाध्यक्ष हुलसी चंद्राकर, नगर पालिका उपाध्यक्ष देवी चंद राठी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि सिरपुर प्राचीन नाम श्रीपुर/श्रिपुरा महानदी के तट पर बसी एक प्राचीन नगरी है, जिसका इतिहास 5वीं से 12वीं सदी तक फैला हुआ है। यह दक्षिण कोसल का प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है और यहां हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों धर्मों के तीर्थ, मठ, मंदिर और विहारों का दुर्लभ संग्रह मिलता है। खुदाई में यहां 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 बुद्ध विहार और 3 जैन विहार के अवशेष मिले हैं। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का सबसे प्रसिद्ध और पुरातन हिंदू मंदिर है, जो 6वीं-7वीं सदी में बनाया गया था।

यह भगवान विष्णु को समर्पित है और प्रमुख रूप से लाल ईंटों से निर्मित है। रानी वासटादेवी ने इसे अपने पति राजा हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया था। इसे एक प्रेम कथा का प्रतीक भी माना जाता है।

शिमला में हजारों सैलानियों ने मनाया नए साल का जश्न, नहीं गिरी बर्फ

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

नए साल के स्वागत के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला एक बार फिर जश्न और उत्साह के रंगों में डूबी नजर आई। देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे हजारों सैलानियों ने नए साल की पूर्व संध्या शिमला में मनाई। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित विंटर कार्निवाल की सांस्कृतिक संध्याओं में पर्यटक देर शाम तक झूमते और थिरकते रहे। आधी रात होते-होते रिज और माल रोड नए साल की बधाइयों, गीत-संगीत और जश्न के शोर से गूंज उठे। हालांकि क्रिसमस के बाद नए साल की पूर्व संध्या पर भी शिमला में बर्फबारी न होने से सैलानी मायूस हुए।

आधी रात तक शिमला पूरी तरह सैलानियों से गुलजार रही। रिज मैदान पर हिमाचली संस्कृति की झलक दिखाती लोकनृत्य प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पर्यटकों को खासा आकर्षित किया। बड़ी संख्या में सैलानी मंच के सामने जमा होकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। कई पर्यटक पारंपरिक हिमाचली धुनों पर खुद भी थिरकते दिखे। जैसे-जैसे रात गहराती गई, जश्न का माहौल और भी रंगीन होता चला गया।

माल रोड और रिज मैदान पर नए साल का काउंटडाउन शुरू होते ही माहौल और रोमांचक हो गया। घड़ी की सुइयां जैसे ही बारह पर पहुंचीं, सैलानियों ने एक-दूसरे को गले लगाकर नए साल की शुभकामनाएं दीं। कहीं मोबाइल कैमरों में यादें कैद की गईं तो कहीं समूह में गीत गाए गए। आधी रात तक माल रोड से लेकर रिज पर रौनक बनी रही और शिमला नए साल की सुबह तक जश्न के रंग में रंगा रहा। पर्यटकों की भारी आमद का असर शहर के होटल उद्योग पर भी साफ दिखा। नए साल के मौके पर शिमला और आसपास के क्षेत्रों के छोटे-बड़े होटल लगभग पूरी तरह पैक रहे। होटल ऑक्यूपेंसी 90 से 100 फीसदी तक पहुंच गई। कालका-शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें भी पूरी तरह भरी रहीं, जिससे पहाड़ों की रानी शिमला की लोकप्रियता एक बार फिर सामने आई।

हालांकि, मौसम ने इस बार सैलानियों को थोड़ी मायूसी भी दी। नए साल की पूर्व संध्या पर शिमला में मौसम बिगड़ा और बादल छाए रहे, ठंड में इजाफा हुआ, लेकिन बर्फबारी नहीं हो सकी। बर्फ देखने की उम्मीद में पहुंचे कई पर्यटक निराश नजर आए। बावजूद इसके ठंडे मौसम और बादलों के बीच शिमला की खूबसूरती ने सैलानियों को जश्न मनाने से नहीं रोका। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिन में बर्फबारी की संभावना जताई है, इससे पर्यटकों को अभी भी उम्मीद बनी हुई है। शिमला व आसपास के इलाकों में नए साल की शुरूआत बादलों से हुई है।

इस बीच सैलानियों की भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पर भी खासा दबाव रहा। 25 से 31 दिसम्बर तक करीब 59 हजार वाहन शिमला पहुंचे। कालका-शिमला नेशनल हाईवे सहित शहर के प्रवेश द्वारों पर लंबा जाम देखने को मिला। कई जगहों पर कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में वाहन चालकों को एक से डेढ़ घंटे तक का समय लगा। शहर की अधिकतर पार्किंगें पूरी तरह भर गईं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नए साल के जश्न के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। शिमला को पांच सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई।

करीब 400 से अधिक पुलिस जवान शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात रहे। भीड़भाड़ वाले इलाकों, रिज मैदान और माल रोड पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोलिंग प्वाइंट्स बनाए गए और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी गई।

बर्फ के इंतजार में नया साल, शिमला, कुफरी और मनाली में मायूसी, एक हफ्ते तक साफ मौसम

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

नए साल का स्वागत बर्फबारी के बीच करने की उम्मीद लेकर शिमला, कुफरी और मनाली पहुंचे हजारों सैलानियों को इस बार भी निराशा हाथ लगी और आधी रात तक जश्न, संगीत व नाच-गाने के बावजूद बर्फ न गिरने से उनका उत्साह फीका पड़ गया। क्रिसमस के बाद नए साल पर भी हिमाचल के इन प्रमुख हिल स्टेशनों में बर्फबारी नहीं हुई, जबकि पूरा विंटर सीजन अब तक सूखा ही बना हुआ है और शिमला, कुफरी व मनाली पहली बर्फबारी को तरस गए हैं।

बीती रात और आज सुबह केवल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ही हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिसमें लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचे भाग शामिल हैं। अटल टनल रोहतांग में भी ताजा हिमपात हुआ, लेकिन बर्फ की यह सफेद चादर शिमला, मनाली और कुफरी तक नहीं पहुंच सकी।

मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला व मनाली में सुबह से बादल छाए हैं, हालांकि इन पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी की कोई ठोस संभावना नहीं दिखी। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूवार्नुमान में साफ किया है कि 2 जनवरी से 7 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा तथा इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। ऐसे में बर्फ का इंतजार कर रहे सैलानियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विभाग ने अगले तीन दिन तक राज्य के निचले और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले दो दिन शीतलहर चलने की चेतावनी भी दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी केवल 400 मीटर दर्ज की गई, बिलासपुर में 500 मीटर, जबकि कांगड़ा और मंडी में 800-800 मीटर दृश्यता रही। बर्फबारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो लाहौल-स्पीति जिले के कोकसर में आज सुबह तक 1.7 सेंटीमीटर और गोंदला में 0.3 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई। पहाड़ों पर हुए इस सीमित हिमपात से प्रदेश का औसतन न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इससे ठंड में इजाफा हुआ है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.8 डिग्री, ताबो में माइनस 3.4 डिग्री, किन्नौर के कल्पा में माइनस 0.4 डिग्री और शिमला जिले के नारकंडा में 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख स्थानों में शिमला का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, सुंदरनगर 5.8 डिग्री, भुंतर 5 डिग्री, धर्मशाला 5 डिग्री, ऊना 8.5 डिग्री, नाहन 7.9 डिग्री, पालमपुर 3 डिग्री, सोलन 3.2 डिग्री, मनाली 5.1 डिग्री, कांगड़ा 5.5 डिग्री, मंडी 6.7 डिग्री, बिलासपुर 7.5 डिग्री, हमीरपुर 5.2 डिग्री रहा।

नए साल की अल सुबह कुल्लू में सड़क हादसे में चार युवाओं की मौत

एजेंसी (हि.स.)
कुल्लू

कुल्लू के एनएच पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक व तीन युवतियों की मौत हो गई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि जहां हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तो वहीं कार में सवार युवक युवतियों को भी गंभीर चोटें पहुंची। सड़क हादसा बुधवार बीती रात करीब दो बजे हुआ जब एक कार भुंतर जिया से कुल्लू शहर की तरफ आ रही थी। कार जब भूतनाथ पुल से करीब 100 मीटर पीछे पहुंची तो कार चालक कार से अपना नियंत्रण खो बैठा और कार पहले सड़क मार्ग से टकराई और उसके बाद कार की दिशा बदल गई और कार सड़क मार्ग के बाईं ओर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई ओर कार में सवार चारों युवक युवतियों बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों द्वारा कड़ी मशक्त के बाद कार में फंसे युवक युवतियों को बाहर निकाला गया और 108 एंबुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर द्वारा तीन घायलों को मृत घोषित कर दिया गया जबकि घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरमल पुलिस दल के साथ मौका पर पहुंच गए और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी।

पुलिस अधीक्षक मदन लाल ने बताया कि मृतको की पहचान सतपाल सिंह (25) पुत्र ध्यान चन्द निवासी चामुण्डा नगर डाकघर ढालपुर तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0), कशिश (20) तेजे राम गांव व डाकघर जलुग्रां तहसील जरी जिला कुल्लू (हि0प्र0), अंकिता (20) पुत्री राकेश कुमार गांव व डाकघर उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) के रूप में हुई है तथा हादसे में घायल रितान्जली उर्फ रुची (20) पुत्री युधीष्ठर गांव व डाकघर सचाणी तहसील भून्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एम्स बिलासपुर में दम तोड़ दिया। पुलिसन ने धारा 281, 125(ए), 106 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बांग्लादेशी नागरिक को बीएसएफ ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंपा

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने जम्मू जिले के गजनसू इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से पकड़े गए एक बांग्लादेशी नागरिक को जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया है। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर नियमित निगरानी के दौरान उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और बाद में उसे कनाचक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गजनसू सीमा पुलिस चौकी के समक्ष पेश किया।

पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 19 वर्षीय शरीफुल इस्लाम भुइयां पुत्र मोजिबुल हक भुइयां निवासी बांग्लादेश के कोमिला जिले के आद्रा इलाके के रूप में की है। प्रारंभिक औपचारिकता पूरी करने के बाद बीएसएफ ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की परिस्थितियों का पता लगाने और अन्य संबंधित विवरणों की पुष्टि करने के लिए उससे पूछताछ जारी है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद रमजान के मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द ही अमित शाह से बातचीत करेंगे

श्रीनगर। राज्यसभा सांसद चौधरी रमजान ने गुरुवार को इस बात पर जोर देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर कोई मतभेद नहीं है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी सांसद आगा रुहुल्लाह न तो पार्टी के खिलाफ हैं और न ही उसके नेतृत्व के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद आयोजित अभिनंदन समारोह के रमजान ने कहा कि पार्टी एकजुट है और अपने उद्देश्यों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मतभेद नही हैं तो वे केवल दृष्टिकोण में हैं आगा रुहुल्लाह युवा चाहते हैं कि काम जल्दी हो। बस यही एक अंतर है। हमारे लक्ष्य और दिशा एक ही हैं लेकिन ऐसे मामलों को साकार होने में समय लगता है रमजान ने कहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद सत्र के दौरान उनकी मुलाकात आगा रुहुल्लाह से हुई और उन्होंने पाया कि वे पार्टी नेतृत्व के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। उन्होंने आगे कहा मैंने उन्हें पार्टी या उसके नेतृत्व के खिलाफ नहीं पाया। वे उन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

संक्षिप्त-समाचार

हिमाचल में पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका, जांच जारी

सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के अंतर्गत नालागढ़ पुलिस थाने के बाहर गली में नए वर्ष के पहले दिन वीरवार को सुबह साढ़े दस बजे के करीब जोरदार धमाका हुआ । इसकी आवाज और तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतों के खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए । क्षेत्र में अफरातफरी मचने के साथ ही दहशत फैल गई है । फिलहाल पुलिस ने इसे किसी प्रकार की आतंकी कारवाई से इनकार किया है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और धमाके के कारणों की जांच की जा रही है । पुलिस अधीक्षक बीबीएन विनोद धीमान मौके पर पहुंचकर कारणों की जांच में जुट गए हैं । इस घटना में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ बताया गया है । इस घटना की संवेदनशीलता के मध्यनजर फोरेंसिक टीम को सूचित किया गया है, टीम के आने के बाद मौके से साक्ष्य एकत्रित कर घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा । इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं । जांच के बाद ही कारणों का खुलासा हो पायेगा ।

काम का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी पर केस दर्ज

शिमला। जिला शिमला के रामपुर थाना क्षेत्र में 43 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने दुष्कर्म का खुलासा करने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी प्रताप राणा पिछले करीब तीन महीनों से काम के बहाने उसके संपर्क में था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने 29 दिसंबर को दो अलग-अलग मौकों पर रामपुर क्षेत्र में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने घटना का खुलासा करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि शिकायत के आधार पर थाना रामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध ड्रोन ड्रॉप बरामद, बीडीएस को बुलाया गया

पुंछ। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को पुंछ जिले के चका दा बाग इलाके में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास से ड्रोन द्वारा गिराए जाने के संदेह में एक खेप बरामद की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में नियमित निगरानी के दौरान यह बरामदगी की गई। सेना को मौके पर एक संदिग्ध बैग भी मिला जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। बरामदगी के बाद बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) को तुरंत मौके पर बुलाया गया ताकि किसी भी संभावित विस्फोटक खतरे की जांच और उसे निष्क्रिय किया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि खेप की प्रकृति और उसमें मौजूद सामग्री की आगे की जांच जारी है।

आशीष कुंद्रा ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य सचिव का पदभार संभाला

कारगिल। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष कुंद्रा ने गुरुवार को औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने डॉ. पवन कोटवाल की जगह ली जो 31 दिसंबर को सेवा से रिटायर हो गए थे। पदभार संभालने के बाद कुंद्रा ने प्रभावी शासन, पारदर्शी प्रशासन और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, सेवा वितरण को बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से विकासात्मक कार्यक्रमों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। टीम वर्क, जवाबदेही और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नए मुख्य सचिव ने कहा कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना प्रशासन की एक प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने सुलभ प्रशासन पर जोर दिया जो प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश के सभी हिस्सों तक पहुंचता है।

कांगड़ी एवं गदयाली नाइट के साथ कांगड़ा वैली कार्निवाल-2025 का समापन

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

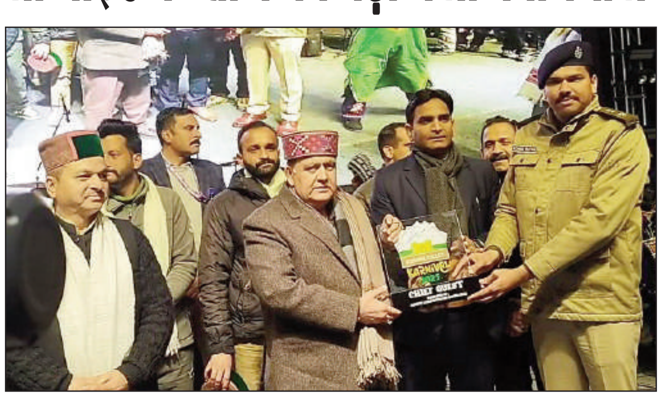

कांगड़ा वैली कार्निवाल-2025 के आठवें एवं अंतिम नाईट बुधवार को स्थानीय लोक-संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित ह्यलोकल कांगड़ी एवं गड्याली नाइटह्न का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांगड़ा घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सशक्त मंच मिला और आठ दिवसीय कार्निवाल का उल्लासपूर्ण समापन हुआ।

इस समापन संध्या में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में कार्निवाल के समग्र आयोजन की सफलताओं को नई ऊँचाइयाँ मिलीं।

कुलदीप पठानिया ने कहा कि कांगड़ा वैली कार्निवाल जैसे आयोजन हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा कार्निवाल ने स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और सामाजिक समरसता को नई पहचान दी है, और भविष्य में यह आयोजन और भी भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए हैं, ताकि देश-विदेश से अधिक से अधिक पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित हों। इसी दृष्टि से पिछले वर्ष से कई नई पहलों की शुरूआत की गई।

कार्यक्रम के दौरान कांगड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों की पारंपरिक लोकनृत्य एवं लोकगीत प्रस्तुत किए गए। कांगड़ी और गदयाली संस्कृति की विशिष्ट झलक पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से देखने को मिली। स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

इसके साथ ही ईशांत भारद्वाज, निशा पंडित और संजीव दीक्षित, हिमांशी और निकेश बड़जात्या ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत मिस एवं मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवाल प्रतियोगिता का फाइनल भी आयोजित किया गया, जिसने विशेष आकर्षण जोड़ा।

इससे पूर्व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कार्निवाल के दौरान आयोजित क्रिकेट टूनार्मेंट के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए।

एसआर-11 को पहले पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, टीएमसी वीरता को दूसरे स्थान पर रहने पर 75 हजार रुपये, तीसरे स्थान पर रहने वाले 9 वारियर्स को 50 हजार रुपये तथा चौथे स्थान पर रहने वाले बैंकर्स 11 को 25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने दी राज्यपाल को नव वर्ष की शुभकामनाएं

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

नव वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी एवं देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर के साथ आज लोक भवन पहुंच कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तथा कमलेश ठाकुर ने लेडी गवर्नर को पारंपरिक हिमाचली शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और समग्र विकास की कामना की। राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धमार्णी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक संजय अवस्थी ने भी राज्यपाल को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं।

मौसम | **कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना**

कश्मीर के पर्यटन स्थलों और घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी ने किया नव वर्ष का स्वागत

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

कश्मीर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों और घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के बीच नव वर्ष का स्वागत हुआ। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग सहित पर्यटन स्थलों पर रात भर ताजा बर्फबारी हुई, जो गुरुवार सुबह तक जारी रही। बर्फबारी को देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी की ओर उमड़ पड़े।

गुरेज की तुलैल घाटी, बांदीपोरा का राजदान टॉप, कुपवाड़ा का मच्छिल और साधना टॉप तथा जोजिला दर्रा जैसे कई ऊंचे इलाकों में भी ताजा बर्फबारी हुई। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का पिछला हिस्सा शाम तक दूर चला जाएगा, जिससे मौसम में धीरे-धीरे सुधार होगा। हालांकि, शुक्रवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बादल छाए रहने के कारण रात का तापमान मौसमी औसत से अधिक रहा और अधिकांश स्थानों पर हिमांक बिंदु से ऊपर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ताजा बर्फबारी के बावजूद घाटी में असामान्य रूप से गर्म शीत ऋतु जारी है, जहां तापमान मौसमी औसत से 1.2 से 6.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बुधवार रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के सामान्य तापमान से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। गुलमर्ग इस क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस पर रहा जो पिछली रात के तापमान से 2.5 डिग्री कम था। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 6.3 डिग्री अधिक था और घाटी के प्रवेश द्वार शहर काजीगुंड में पारा 2 डिग्री सेल्सियस पर रहा जो सामान्य तापमान से 5 डिग्री अधिक था।

कश्मीर घाटी वर्तमान में ह्यचिल्लई-कलांह्न नामक 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि से गुजर रही है। इस दौरान रात का तापमान आमतौर पर हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे गिर जाता है। हालांकि, वर्तमान आंकड़े सामान्य पैटर्न से भिन्न हैं। इस चरम मौसम के दौरान हिमपात की संभावना सबसे अधिक और प्रबल होती है। हालांकि, घाटी के मैदानी इलाकों में इस मौसम में अभी तक हिमपात नहीं हुआ है।

जम्मू-कश्मीर की संस्थाओं के पतन के लिए पीडीपी जिम्मेदारः तनवीर सादिक

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक तनवीर सादिक ने गुरुवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर तीखा हमला किया और इसे 2014 के बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक और संस्थागत ढांचे के ₹व्यवस्थित क्षरण₹ के लिए जिम्मेदार ठहराया। सामुदायिक भवन की आधारशिला रखने के बाद श्रीनगर के रैनावारी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए सादिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को नुकसान 2019 में नहीं बल्कि बहुत पहले शुरू हुआ था जब पीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन करके सिद्धांत के बजाय सत्ता को चुना। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने बीजेपी को बाहर रखने के लिए लोगों से वोट मांगे लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उसी ताकत के साथ गठबंधन किया जिसके खिलाफ उन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी। उस क्षण ने जम्मू-कश्मीर के पतन की शुरूआत को चिह्नित किया । सादिक ने कहा कि पीडीपी-भाजपा शासन के दौरान लिए गए प्रमुख फैसलों से संस्थाएं कमजोर हुईं और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति कमजोर हुई। उन्होंने कहा कि जिस दिन पीडीपी ने सचिवालय की चाबियां सौंपी उसी दिन क्षरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जीएसटी, सरफेसी और संस्थागत कमजोरी एक के बाद एक शुरू हो गई।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
नवोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेंजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने और दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है, इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल (ज्वेल्ल उंस्र्स') पर अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल का भी ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों -बेटियों के लिए, शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है। अब इस योजना को सामाजिक विकास के साथ जोड़ा जाएगा और इसके लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को जोड़ा गया है। इसके तहत, वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा, बशर्ते कि उन माताओं ने विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बच्चों की शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया है। संशोधन के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे है, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लेकर आते है, ऐसी माताओं को भी अब दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने के उद्देश्य से भी भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा एक से चार तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही, बच्चों में कुपोषण या एनीमिया को रोकने के लिए भी पहल की गई है। इसके तहत, पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त था, वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। आयु और रिहायशी प्रमाण पत्र के मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, उपरोक्त सभी श्रेणियों के तहत यह लाभ केवल 3 बच्चों तक ही मिलेगा। जिन महिलाओं के तीन से अधिक बच्चे है वे इस श्रेणी के लिए अपात्र होंगी। इसके साथ ही, महिलाओं व उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है। वर्तमान में जो 2100 रुपए की राशि बहन - बेटियों के खातों में जा रही है, अब इस राशि में से 1100 रुपए सीधे महिलाओं को मिलेंगे और 1000 रुपए सरकार रेकरिंग डिपॉजिट/फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित लाभार्थी को मिलेगा। आरडी/एफडी की अवधि सरकार द्वारा तय की जाएगी जोकि पांच साल से अधिक नहीं होगी। इसका एक स्टर भी प्रत्येक महिला को हर माह जाएगा। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची ग्राम सभाओं में जारी की जाएगी। यदि कोई आपत्ति दर्ज करवाई जाती है तो संबंधित का नाम काट दिया जाएगा। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है। इसमें से 8 लाख महिलाएं को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक सरकार ने दो किस्तों में लगभग 250 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में स्वर्गीय ए.एस.आई. श्री संदीप कुमार लाठर की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को कैम्पस स्कूल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में पी.जी.टी. गणित (ग्रुप-बी) के पद पर नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई है। यह केवल असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पात्र आश्रित को मानवीय एव नीतिगत राहत प्रदान करने तक सीमित है। यह मामला एक अपवादात्मक प्रकरण के रूप में माना गया है तथा इसे भविष्य में मिसाल नहीं माना जाएगा। हरियाणा में अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन-देन के लिए विनिमय विलेखों (एक्सचेंज डीड्स) के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7अ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को ह्यहरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2025ह्न जारी कर मंजूरी प्रदान की गई।

हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर सीईटी फेज-2 भर्ती का विज्ञापन जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी करते हुए उव्ल्ल फेज-क्क के अंतर्गत हरियाणा पुलिस कांस्टेबल (पुरुष, महिला एवं हरियाणा रेलवे पुलिस) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए हैं। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 25 जनवरी 2026 की रात्रि 11:59 बजे तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि बीसीए, बीसीबी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सहायक प्रमाण-पत्र 01 अप्रैल 2025 से 25 जनवरी 2026 के बीच जारी होना अनिवार्य है, जबकि डीएससी एवं ओएससी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सहायक प्रमाण-पत्र 13 नवंबर 2024 के बाद और अंतिम तिथि तक जारी होना चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि पूर्व सैनिक के पारिवारिक सदस्यों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र 12 जनवरी 2025 के बाद जारी अथवा नवीनीकृत होना आवश्यक है।

आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या 14/2024 के अंतर्गत आवेदन किया था, उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नया आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा उन्हें नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा तिथि की जानकारी आयोग द्वारा बाद में अलग से जारी की जाएगी। श्री हिम्मत सिंह ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों एवं संलग्नकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें और किसी भी सीएससी सेंटर या अन्य माध्यम से आवेदन न करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर वह निरस्त हो जाता है, तो उसे सुधारने के लिए कोई करेक्शन पोर्टल नहीं खोला जाएगा। ऐसा आवेदन अंतिम माना जाएगा और स्वतः निरस्त हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए आवेदन अत्यंत सावधानीपूर्वक स्वयं ही भरें।

वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करेगी हरियाणा सरकार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार बुजुर्गों को मान-सम्मान देने और समाज निर्माण में उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए वर्ष 2025-26 के लिए वरिष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एव पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना समाज सेवा, कला, खेल और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुजुर्गों को एक नई पहचान और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों जैसे शतवर्षीय पुरस्कार, श्रेष्ठ माता, शौर्य और बहादुरी, आजीवन उपलब्धि के साथ-साथ वरिष्ठ पेंटर, मूर्तिकार, संगीतकार और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, श्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार, श्रेष्ठ वृद्धाश्रम और श्रेष्ठ दैनिक देखभाल केन्द्र को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में कला और खेल श्रेणियों के लिए प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये निर्धारित है। इसी प्रकार, संस्थागत श्रेणियों (जैसे श्रेष्ठ पंचायत और एनजीओ) के लिए प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये, द्वितीय 75,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपनी उपलब्धियों के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों सहित विभाग के पोर्टल पर 12 जनवरी, 2026 की रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जनहित में बड़ा फैसला- जनस्वास्थ्य के मामलों में सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी: आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि हरियाणा में मानव उपयोग के लिए इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में 100 मिलीग्राम से ज्यादा निमेसुलाइड वाली सभी ओरल फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य लोगों को संभावित दुष्प्रभावों से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में केवल सुरक्षित और प्रमाणित दवाओं का ही उपयोग हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य के मामलों में सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से लोगों के हित और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि दवाओं का उद्देश्य रोगियों को राहत देना है, न कि उनके स्वास्थ्य को खतरे में डालना। जब वैज्ञानिक साक्ष्य किसी दवा से जोखिम की ओर संकेत करते हैं और सुरक्षित विकल्प मौजूद हों, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह जनहित में ठोस निर्णय ले।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने दवा निमार्ताओं, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों और मेडिकल स्टोरों को इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही, नियमित निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था की गई है तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से भी अपील की कि वे निर्धारित चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित वैकल्पिक दवाओं का ही परामर्श दें और मरीजों को सही जानकारी प्रदान करें। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश ने जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दिया है, जिसके तहत इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड युक्त सभी ओरल फामुर्लेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक तथ्यों के गहन मूल्यांकन और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड वाली ओरल दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इसी के अनुरूप हरियाणा सरकार ने इस अधिसूचना को बिना विलंब लागू किया है।

केंद्र सरकार की अधिसूचना को तत्परता से लागू कर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने और लोगों की सेहत की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संक्षिप्त-समाचार

हरियाणा सरकार ने राजकीय महाविद्यालय बौंद कलां का नाम बदलने को दी मंजूरी: महीपाल ढांडा

चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जिला चरखी दादरी के राजकीय महाविद्यालय बौंद कलां का नाम परिवर्तित कर अमर शहीद सूबेदार बनवारी सिंह राजकीय महाविद्यालय बौंद कलां करने को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह निर्णय उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की स्वीकृति के बाद लिया गया है। शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि शहीद सूबेदार बनवारी सिंह 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान युद्ध (ऑपरेशन कैक्टस लीली) के दौरान राजपूत रेजिमेंट में रहते हुए शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि यह बदलाव न केवल शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करेगा, बल्कि विद्यार्थियों को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर भी प्रदान करेगा।

हरियाणा कैबिनेट ने 2002 में नियुक्त 347 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को ओपीएस और अन्य लाभ किए प्रदान

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लाभ देने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करना और समान पद वाले कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। इन ड्राइवरों को वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था और बाद में वर्ष 2006 में हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-उ) हरियाणा रोडवेज सेवा नियम, 1995 (समय-समय पर संशोधित), के तहत रेगुलर किया गया था। हालांकि, जनवरी 2014 में सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए आपसी समझौते में केवल 1 जनवरी, 2003 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को ही शामिल किया गया था, इसलिए वर्ष 2002 में नियुक्त ड्राइवरों को यह लाभ नहीं मिल पाए थे, जिससे जूनियर ड्राइवरों को अपने सीनियर्स की तुलना में ज्यादा सैलरी और पेंशन लाभ मिल रहे थे। इस फैसले से, वर्ष 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरूआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। शुरूआती नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना करके एसीपी इत्यादि, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 का लाभ प्रदान करने, जनरल प्रोविडेंट फंड खाते खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त, 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर, 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी अन्य कट-ऑफ तारीख से मिलेंगे।

विकसित राष्ट्र का सपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण समावेशी समाज,और राष्ट्रहित सर्वेपरी के द्वारा सम्भव है: प्रो. नरेन्द्र कुमार

सिवानी मंडी। स्थानीय सेठ मेघराज जिंदल राजकीय महाविद्यालय, सिवानी में नव वर्ष पर महान वैज्ञानिक सत्येन्द्र नाथ बोस की जयंती और विश्व परिवार दिवस का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में महान वैज्ञानिक सत्येन्द्रनाथ बोस जयंती समारोह में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ,दिल्ली के प्रोफेसर नरेन्द्रा कुमार ने शिरकत की वहीं अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भूपसिंह गौड ने की। जयंती पर प्रोफेसर प्रवीण कुमार ने कहा कि 1 जनवरी को हम भारत के महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सत्येन्द्र नाथ बोस की जयंती मनाते हैं, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। सत्येन्द्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी, 1894 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और अध्यापन किया। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकीः उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसने बोसॉन नामक कणों के एक वर्ग की नींव रखी।उनका दूरदर्शी योगदान रहा जैसे बोस ने पदार्थ की एक नई अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट की भविष्यवाणी की।

नव वर्ष पर फरीदाबाद को बड़ी सौगात, कृष्ण पाल गुर्जर ने हॉस्पिटल ऑन व्हील्स को दिखाई हरी झंडी

- एक्स-रे, लैब टेस्ट, ईएनटी जांच सहित दर्जनों सुविधाओं से लैस है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स
- उद्योगों में जाकर मजदूरों की होगी स्वास्थ्य जांच, समय और खर्च दोनों की होगी बचत : कृष्ण पाल गुर्जर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने नव वर्ष के आगमन पर वीरवार को फरीदाबाद में सेक्टर-28 स्थित अपने कार्यालय परिसर से ह्लहॉस्पिटल ऑन व्हील्सह्व दो अत्याधुनिक चिकित्सा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के माध्यम से उन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, जहां अस्पतालों की पहुंच सीमित है। इन बसों में प्राथमिक उपचार, जांच सुविधाएं तथा आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे आम नागरिकों को घर के नजदीक स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। यह हरियाणा का पहला ह्लहॉस्पिटल ऑन व्हील्सह्व है, जो पूरी तरह आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है। यह मोबाइल मेडिकल वैन एक चलते-फिरते अस्पताल के रूप में कार्य करेगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि इस वैन में एयर कंडीशनिंग, जनरेटर, एक्स-रे मशीन, लैब टेस्टिंग की सुविधा, ब्लड टेस्ट, ईएनटी जांच सहित दर्जनों प्रकार की आवश्यक चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अत्याधुनिक वैन के माध्यम से मजदूरों को एक ही स्थान पर सभी जरूरी स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा, जो दिन-रात औद्योगिक इकाइयों में कड़ी मेहनत करते हैं और समय के अभाव में अस्पताल जाकर नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाते। अब अस्पताल स्वयं मजदूरों के पास पहुंचेगा। यह मोबाइल मेडिकल वैन उद्योगों में जाकर वहीं पर श्रमिकों की जांच करेगी और उन्हें समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों, विशेषकर गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी सोच के साथ देश की सबसे बड़ी बुनियादी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत झ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया, जिसके तहत आज देश के लगभग 70 करोड़ नागरिक हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर रहे हैं।

हरियाणा में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा, मत्स्य पालन, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, उद्योग, विकास एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और मत्स्य विश्वविद्यालयों के कुलपति भी समिति के सदस्य होंगे।

समिति में नाबार्ड के राज्य प्रतिनिधि तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार की स्वीकृति से अन्य प्रासंगिक सदस्यों को भी समिति में शामिल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत गठित यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि चयनित जिलों में परियोजना मोड में संचालित सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों तथा विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित हो। इसके साथ ही, जिला योजनाओं में आवश्यक आदानों (इनपुट्स) के साथ-साथ विपणन तथा मूल्य संवर्धन के पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही यह अपेक्षा की गई है कि राज्य के संबंधित विभाग इन जिलों के उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग तथा मूल्य संवर्धन के लिए विशेष रूप से सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें।

राज्य स्तरीय समिति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि फील्ड लेवल के पद भरे जाएं, धनराशि समय पर जारी हो तथा सभी एजेंसियों द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विभाग की वार्षिक योजनाएं वित्त वर्ष शुरू होने से पूर्व ह्यप्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की वार्षिक योजना के साथ समेकित की जाएं।

सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पांच सेवाएं राइट टू सर्विस के दायरे में

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पांच सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल करते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए सीएलयू अनुमति (सरकार की सक्षमता को छोड़कर) के लिए सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार, सीएलयू अनुमति प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति के लिए 90 दिन की समय-सीमा तय की गई है। कब्जा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, अपराध की संलिप्तता न होने की स्थिति में 60 दिन और संलिप्तता होने की स्थिति में 90 दिन की समय-सीमा तय की गई है।

इन सेवाओं के लिए जिला नगर योजनाकार या वरिष्ठ/मुख्य नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। वहीं, मुख्य नगर योजनाकार अथवा वरिष्ठ नगर योजनाकार को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लिए लाइसेंस सभी दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण के वरिष्ठ नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। वहीं, मुख्य नगर योजनाकार को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।

2030 तक अरावली संरक्षण के लिए हरियाणा की ठोस कार्ययोजना, ग्रीन वॉल परियोजना पर तेजी से काम: राव नरबीर सिंह

- मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण व सूखे की चुनौती से निपटने में अरावली बनेगी प्राकृतिक ढाल
- प्रधानमंत्री के मिशन 'लाइफ' और ह्यएक पेड़ मां के नाम से प्रेरित योजनाओं को हरियाणा में मिल रहा विस्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के प्रति पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार हरियाणा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2030 तक क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।

वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा वह पावन भूमि है जहाँ से वैदिक सभ्यता की शुरूआत हुई, वेदों की रचना हुई और जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व गीता का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) तथा ह्यएक पेड़ माँ के नाम जैसी ऐतिहासिक पहलें शुरू की गईं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया है। ये पहलें वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर लोगों को स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने ऑक्सी वन, प्राण वायु देवता योजना और वन मित्र योजना जैसी अभिनव पहलें शुरू की हैं, जिनके माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये योजनाएं अरावली संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कड़ी साबित होंगी।

वन मंत्री ने बताया कि दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी, बाढड़ा, लोहारू और केरू क्षेत्रों में जाटी एवं रोहिड़ा जैसे स्थानीय वृक्षों के संरक्षण के लिए किसानों को प्राण वायु देवता योजना की तर्ज पर वार्षिक मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, ताकि अरावली क्षेत्र में हरियाली बनी रहे और स्थानीय लोग संरक्षण से सीधे जुड़ सकें। राव नरबीर सिंह ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व है। यह पर्वतमाला मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करती है तथा जैव विविधता, जल सुरक्षा और जलवायु संतुलन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अरावली भूजल पुनर्भरण, वायु गुणवत्ता सुधार, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में आजीविका को सहारा देने में अहम भूमिका निभाती है।

उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला को विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के परिदृश्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जो मानव और प्रकृति के गहरे संबंध का प्रतीक है। वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित सभी अरावली राज्यों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम अरावली जैव विविधता पार्क जैसी परियोजनाएं पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का सफल मॉडल हैं, जिसे भारत का पहला ओईसीएम (अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय) भी घोषित किया गया है, जो आईयूसीएन के वैश्विक दिशानिदेर्शों की पुष्टि करता है।

उन्होंने कहा कि जहां युवाओं को इस नेक कार्य से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में ग्राम स्तर पर वन मित्रों की नियुक्ति की गई है। वहीं, प्राण वायु देवता योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को ₹2500 वार्षिक पेंशन दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में वायु शुद्धता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण रोकने के लिए ऑक्सी वन स्थापित किए जा रहे हैं।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर दी गई नई परिभाषा का हरियाणा स्वागत करता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अरावली क्षेत्र के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से को संरक्षित रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार का उद्देश्य अरावली क्षेत्र में हरित रोजगार सृजन, जन भागीदारी बढ़ाना और जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरण अनुकूल संसाधन प्रबंधन को सशक्त बनाना है।

संपादकीय

मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का कड़वा सचः दूषित पानी ने ली 10 जानें, स्वच्छता रैंकिंग पर उठे गंभीर सवाल

मध्य प्रदेश के जिस शहर को देश का सबसे 'स्वच्छ' शहर होने का गौरव वर्षों से मिलता रहा है, वहीं दूषित पानी पीने से कम से कम दस लोगों की मौत की घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। 1 जनवरी 2026 को सामने आई यह त्रासदी साफ बताती है कि चमकदार स्वच्छता रैंकिंग, पुरस्कार और प्रचार के पीछे जमीनी हकीकत कितनी भयावह हो सकती है। यह मामला केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में शहरी स्वच्छता, पेयजल प्रबंधन और जनस्वास्थ्य तंत्र की गहरी खामियों की ओर इशारा करता है। जानकारी के अनुसार, शहर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में लोग उल्टी, दस्त, बुखार और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। शुरूआत में इन लक्षणों को मौसमी बीमारी मानकर नजरअंदाज किया गया। स्थानीय स्तर पर न तो पानी की गुणवत्ता की तुरंत जांच कराई गई और न ही स्वास्थ्य विभाग ने किसी बड़े खतरे की आशंका जताई। लेकिन जब एक के बाद एक मौतें होने लगीं, तब प्रशासन हरकत में आया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पेयजल आपूर्ति में गंभीर रूप से दूषित पानी पहुंच रहा था, जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया और संभवतः सीवेज का मिश्रण था।यह स्थिति उस शहर में सामने आई, जिसे लंबे समय से 'क्लीन सिटी' के रूप में देशभर में उदाहरण बनाकर पेश किया जाता रहा है। सवाल यह है कि जिस शहर की स्वच्छता व्यवस्था की तारीफ राष्ट्रीय मंचों पर होती रही, वहीं बुनियादी जरूरत यानी सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था इतनी लचर कैसे साबित हुई। यह घटना कई स्तरों पर प्रशासनिक और संस्थागत विफलता की कहानी कहती है।सबसे पहली और बड़ी विफलता जल आपूर्ति तंत्र की है। आधुनिक शहरों में पाइपलाइन नेटवर्क, जल शोधन संयंत्र और पानी की नियमित गुणवत्ता जांच एक अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बावजूद दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचता रहा। यह सवाल बेहद गंभीर है कि जब बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे थे, तब पानी की गुणवत्ता की तत्काल और व्यापक जांच क्यों नहीं की गई। क्या जल शोधन संयंत्रों की निगरानी केवल कागजों तक सीमित थी? यदि समय पर परीक्षण और निगरानी होती, तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थीं।दूसरी बड़ी विफलता प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही की है। स्वच्छता रैंकिंग और पुरस्कार मिलने के बाद अक्सर स्थानीय निकायों में आत्मसंतोष की भावना घर कर जाती है। अधिकारी उपलब्धियों का प्रचार करने में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि बुनियादी सेवाओं की सतत निगरानी कमजोर पड़ जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही नजर आता है। शहर की 'स्वच्छ' छवि बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मूल जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया गया।तीसरा और सबसे चिंताजनक पहलू जनस्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी से जुड़ा है। जब बड़ी संख्या में लोग एक जैसे लक्षणों के साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचने लगे, तब यह संकेत था कि कोई सामूहिक स्वास्थ्य संकट उभर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों को अलर्ट मोड में आकर कारणों की जांच शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य तंत्र ने भी शुरूआत में इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। इस देरी का खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।इस त्रासदी ने 'स्वच्छ भारत मिशन' जैसे राष्ट्रीय अभियानों की मूल्यांकन पद्धति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वच्छता को अक्सर केवल साफ सड़कों, कूड़ा प्रबंधन और दृश्यात्मक साफ-सफाई तक सीमित कर दिया जाता है। जबकि सुरक्षित पेयजल, सीवेज प्रबंधन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य भी स्वच्छता के उतने ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी शहर को 'स्वच्छ' घोषित करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां की जल आपूर्ति प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की ठोस व्यवस्था मौजूद है।घटना के बाद राज्य सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दूषित पानी से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का इलाज पूरी तरह सरकारी खर्च पर किया जाएगा। प्रभावित इलाकों में मुफ्त इलाज, बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये राहत कदम खासतौर पर उन क्षेत्रों में लागू किए गए हैं, जहां दूषित पानी की आपूर्ति से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन भी किया है। इस समिति की अगुवाई आईएएस अधिकारी नजीवन पंवार कर रहे हैं, जबकि इसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रदीप निगम और एमवाई अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेश राय को शामिल किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह घटना के सभी तकनीकी, प्रशासनिक और स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं की गहन जांच करे और यह स्पष्ट करे कि दूषित पानी की आपूर्ति कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुझाव भी दिए जाएं।मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों की संख्या, अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति और राहत कार्यों की पूरी जानकारी तय समयसीमा में पेश की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति तथा मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं।अंततः, मध्य प्रदेश के इस 'स्वच्छ' शहर में हुई मौतें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि विकास और स्वच्छता की हमारी परिभाषा कितनी अधूरी और सतही है। अगर साफ सड़कों और चमकदार रैंकिंग के बीच दूषित पानी लोगों की जान ले रहा है, तो ऐसी स्वच्छता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। यह घटना पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि स्वच्छता और विकास के दावों को केवल आंकड़ों और पुरस्कारों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की सुरक्षा को केंद्र में रखा जाए। यदि इस त्रासदी से सबक लेकर व्यवस्था में वास्तविक सुधार नहीं किए गए, तो भविष्य में ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे और 'स्वच्छता' एक खोखले नारे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी।

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हमले की घटनाएं, सेक्युलर दलों की चुप्पी

मृत्युंजय दीक्षित (हि.स.)

अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक प्रदर्शनों के चलते अपना देश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर आक्रमण, हत्या और आगजनी की भीषण घटनाएं हुईं क्योंकि हिन्दुओं को उनकी पार्टी का समर्थक माना जाता है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। यूनुस के आते ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई और भारत तथा हिन्दू विरोधी आग भड़काने में जुट गई। दिसंबर 2025 में भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद यह आग और भड़क गई। अब ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाकर हिन्दुओं की हत्याएं की जा रही हैं। हिन्दू घरों में बाहर से ताला लगाकर आग लगाई जा रही है। इन सभी क्रूर आपराधिक घटनाओं को यूनुस सरकार का मौन समर्थन है जिससे हिन्दू जान बचाकर भाग तक नहीं पा रहा है।

बांग्लादेश हिंदू समाज के नरसंहार की भूमि बन चुका है। विभाजन के समय बांग्लादेश में हिन्दू जनसँख्या 23 प्रतिशत थी। 1974 की जनगणना में यह घटकर मात्र 13.5 प्रतिशत रह गई थी और अब मात्र 7.96 प्रतिशत है। हिन्दुओं पर हो रहे धार्मिक अत्याचारों का यही हाल रहा तो बांग्लादेश में हिन्दू पूरी तरह से लुप्तप्राय हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में अल्पसंख्यकों पर 47 हमले दर्ज किए गए जो 2023 में बढ़कर 302 हो गए और फिर 2024 में तेजी से बढ़कर 3200 हो गए।

दिसंबर माह में ही पहले दीपू चन्द्र दास और फिर अमृत मंडल को भीड़ ने ईशनिंदा के नाम पर बर्बरता से मार डाला। चटगांव मे हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई। घटनास्थल से एक धमकी भरा नोट मिला जिसमें हिन्दुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था और गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई। हादी की मौत का बदला लेने के लिए भीड़ हिन्दुओं के खून की प्यासी होकर हथियारों के साथ सड़कों पर घूम रही है। बांग्लादेश में प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और अब तक 850 से अधिक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। केवल ताजा हिंसा में ही अभी तक 200 से अधिक हिन्दुओं की हत्याएं और 170 से अधिक हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में साल 2022 से 2024 के बीच हिन्दू अल्पसख्यकों पर हमलों के मामले आठ गुना बढ़ गए हैं।

बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में जिस प्रकार से वृद्धि देखी जा रही है वह केवल तात्कालिक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है अपितु देश की सामाजिक तथा जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के लिए दशकों से किए जा रहे कट्टर इस्लामी राजनीतिक प्रयासों का परिणाम भी है।

बांग्लादेश मे हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। शेख हसीना की सरकार के समय भी हमले होते थे, विशेषकर जब हिन्दुओं के पवित्र नवरात्र प्रारंभ होते थे तब ईशनिंदा की झूठी अफवाहें फैलाकर दुर्गा पंडालों पर हमले किए जाते थे और उनमें तोड़फोड़ की जाती थी। अब अंतर यह आ गया है कि इन घटनाओं का नियंत्रण पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई व कट्टरपंथी अराजक तत्वों के हाथ में आ गया है।

बांग्लादेश मे ईशनिंदा कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। आठ ऐसे अवसर रहे हैं जब हिंदुओं पर ईशनिंदा के नाम पर भयानक हमले किए गए। सुनामगंज में एक फेसबुक पोस्ट के बाद पूरा हिंदू गांव तबाह कर दिया गया। रंगपुर के गंगा चरा में एक हिंदू युवक पर आरोप लगाने के बाद दंगाइयों ने 22 हिंदू घरों को ध्वस्त कर दिया। खुलना, बारिशाल, मौलवी बाजार, फरीदपुर, चांदपुर और कुमिल्ला जैसे जिलों मे भी हिंदुओं के साथ भयानक घटनाएं घटी हैं।

मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से हिन्दुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला वास्तव में हिन्दुओं रक्त का प्यासा हो गया है जो उस्मान हादी के अंतिम संस्कार की जनसभा में कहता है कि 'हादी तुम जहां कहीं भी हो हम तुम्हारे हर सपने को अवश्य पूरा करेंगे।' यह भाषण यूनुस की खतरनाक मंशा का संकेत कर रहा है।

बांग्लादेश इस बात का प्रमाण है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वहां पर अन्य अल्पसंख्यक समाज का रहना दूभर हो जाता है। आज बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 91.08 प्रतिशत हो चुकी है और अल्पसंख्यक हिंदू समाज पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है।

बांग्लादेश के कट्टरपंथी देश में शरीयत का कानून लागू करना चाहते हैं। वे हिंदू महिलाओं को माथे पर बिंदी न लगाने, साड़ी न पहनने और बुर्का पहनने को कह रहे हैं और ऐसा न करने पर बलात्कार तथा परिवार को मारने की धमकियां दे रहे हैं। बांग्लादेश में भारत-बांग्लादेश के मध्य मैत्री को मजबूती प्रदान करने के लिए जिन सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की गई थी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे कलाकारों पर हमला किया जा रहा है। जगह-जगह हिन्दुओं का नरसंहार कर अस्तित्व समाप्त करने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस्मान हादी की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की जाती है किंतु हिन्दू नरसंहार पर चुप्पी साध ली जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, बांग्लादेशी हिन्दुओं के लिए कहा था कि अगर बाइडेन की जगह उन्हें चुना गया होता तो आज वहां के हालात ऐसे न होते किंतु ट्रंप अब शांत हैं और अमेरिका से हिंदुओं की हत्याओं की निंदा करने का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। कनाडा की संसद में एक महिला सांसद ने हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई है, कुछ और देशों से भी आवाज उठ रही है किंतु वह नाकाफी है। बांग्लादेश में हिन्दुओं के नरसंहार पर दुनिया भर में मानवाधिकार का हल्ला मचाने वालों ने चुप्पी साध ली है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

जब्ती करों से लोक-केंद्रित सुधार तकः 2025 में भारत की कर संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव

1930 में, महात्मा गांधी द्वारा नमक कर की अवज्ञा ने उजागर किया था कि कैसे दमनकारी कर प्रणाली नागरिक को राज्य से दूर कर सकती है। यह एक चेतावनी थी कि जब कर मनमाने या अत्यधिक होते हैं, तो वे विश्वास और सामाजिक सम्पर्क को कमजोर करते हैं। चार दशक बाद, भारत में एक और चरम स्थिति देखी गई, जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आयकर के स्तर को आश्चर्यजनक रूप से 97.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

इस परम्परा ने करदाताओं और राज्य के बीच गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। दशकों तक, भय के कारण अनुपालन होता रहा। इसने सक्रिय योगदान देने के बजाय टालमटोल को प्रोत्साहित किया। इसी पृष्ठभूमि में मोदी सरकार के कर सुधार, जो 8 वर्ष पहले आरंभ हुए और 2025 में निर्णायक रूप से आगे बढ़े, अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक हैं।

इस बदलाव में अंतर्निहित लाफर कर्व का तर्क यह है कि कम कर दरें राजस्व सृजन के लिए उप-इष्टतम हैं और कर आधार का विस्तार करती हैं। इस प्रकार भारत के 2025 के कर सुधार न केवल राजकोषीय परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि एक दार्शनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उत्पीड़न से सहयोग तक और अविश्वास से लेकर राज्य और नागरिक के बीच एक नया सामाजिक अनुबंध है।

जीएसटी से पहले की वास्तविकताः विखंडन, रिसाव और अविश्वास

वैट शासन के दौरान, अप्रत्यक्ष करों की बहुलता ने व्यापक स्तर पर भ्रम पैदा किया, राज्यों ने 0 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के एकसमान स्लैब को खत्म करते हुए बार-बार वैट दरों में बदलाव किया।

वास्तव में, स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, राज्यों ने अतिरिक्त शुल्क लगाने के विरूद्ध अपनी 2010 की रिपोर्ट में कैग की सुस्पष्ट सलाह की अनदेखी कर दी, फिर भी प्रवेश कर और स्थानीय अधिभार जारी रहे। इसने भ्रम और विखंडन पैदा किया और प्रत्येक राज्य ने अपने स्वयं के अनुपालन नियमों, दंड और प्रक्रियाओं को लागू किया।

इसके गंभीर परिणाम हुए। कमजोर जांच और असंगत प्रवर्तन ने कर चोरी को प्रोत्साहित किया। हर दो डीलरों में से एक ने कर चोरी करने का प्रयास किया और सिर्फ एक मामले में ही, सात डीलरों को उचित दस्तावेज के बिना 1,026 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (2025): कार्यनीति के रूप में सरलता

वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरूआत ऐतिहासिक थी। इसने भारत को एकल बाजार में समेकित किया, व्यापक करों को समाप्त कर दिया और एक पारदर्शी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की नींव रखी। यद्दिप, दरों और वर्गीकरण में अस्पष्टता के कारण विवाद पैदा हुए और निस्संदेह अनुपालन के साथ-साथ पंजीकरण में भी भारी समस्याएं रहीं।

उदाहरण के लिए, वस्त्र क्षेत्र में धुलाई और रंगाई जैसी सेवाओं पर 'जॉब वर्क सर्विसेज' के हिस्से के रूप में 5 प्रतिशत कर लगाया गया था, जबकि ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और रासायनिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं पर 18 प्रतिशत का कर लगाया गया था। इससे वर्गीकरण को लेकर गंभीर भ्रम और कर विवाद पैदा हो गए।

इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने 2025 में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत की, जो जीएसटी के लॉन्च के बाद से सबसे सार्थक सरलीकरण प्रदान करते हैं। इस प्रणाली को दो स्पष्ट स्लैब, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में युक्तिसंगत बनाया गया था। साथ ही, वस्तुओं के वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया गया, अनुपालन को सरल बनाया गया और पंजीकरण को सुगम बनाया गया।

पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सक्रिय रूप से व्यवसायों और राज्यों की बात सुनी है और राज्यों को कार्यान्वयन में समान भागीदार माना है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि सुधारों को सुचारू रूप से लागू किया जाए।

2025 के जीएसटी सुधारों ने करों को सरल बनाने से कहीं अधिक काम किया; उन्होंने कई सेक्टरों में मांग को सीधे तौर पर प्रेरित किया।

भारत में दीपावली के अवसर पर 6.05 ट्रिलियन रुपए की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक है। एक दशक से अधिक समय में यह इसकी सबसे मजबूत नवरात्रि बिक्री रही है। साथ ही, अक्टूबर 2025 में ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री 40.5 प्रतिशत बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

जिन आलोचकों ने यह तर्क दिया था कि जीएसटी को सरल बनाने और दरों को तर्कसंगत बनाने से कर राजस्व में कमी आएगी, वे भी गलत साबित हुए। अक्टूबर-नवंबर 2025 में, जीएसटी में महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद, सकल जीएसटी संग्रह 2024 में इसी अवधि की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक था।

जीएसटी दरों में कटौती और आयकर छूट की सीमा में वृद्धि से परिवारों को सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 0 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो 18 प्रतिशत से कम है। इसका अर्थ है कि 20,000 रुपये के बेस प्रीमियम पर पहले 3,600 रुपये जीएसटी (18 प्रतिशत) था, जिससे 23,600 रुपये देय था। छूट के बाद, 20,000 रुपये के भुगतान पर सीधे 3,600 रुपये की बचत है।

जीएसटी में सुधार से किराने का सामान और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के घरेलू बिलों में 13 प्रतिशत की बचत होगी, जबकि एक छोटी कार का खरीदार लगभग 70,000 रुपये बचा सकता है। एसी खरीद में 2,800 रुपये की बचत होगी क्योंकि इन वस्तुओं की जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाकर और आवश्यक एवं आकांक्षी दोनों वस्तुओं पर कर के बोझ को कम करके, सरकार ने आत्मविश्वास से व्यय करने और निरंतर मांग का वातावरण सृजित किया।

मध्यम वर्ग के लिए कर में महत्वपूर्ण लाभ

भारत की आयकर यात्रा इसके आर्थिक विकास को दर्शाती है। इंदिरा गांधी के युग में कर की दर 97.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और कर चोरी और अविश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। दशकों बाद, उदारीकरण के बावजूद, 2014 में राहत मामूली रही; आयकर छूट को 2 लाख रुपये तक सीमित कर दिया गया था, जो शहरीकरण की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं था।

मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को निरंतर कम किया है, प्रासंगिक उपायों पर नीतिगत स्थिरता को प्राथमिकता दी है। पिछले दशक में आयकर छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपये से बढ़कर 2025 में 12 लाख रुपये हो गई है, जो 6 गुना राहत प्रदान करती है।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, 75,000 रुपये की मानक कटौती के बाद, प्रभावी शून्य-कर सीमा अब 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा जबकि 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को टैक्स के रूप में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

नमक कर से लेकर आयकर की जब्ती दरों तक, भारत का इतिहास बताता है कि त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली विश्वास और विकास को कमजोर करती है। मोदी सरकार के 2025 के कर सुधार उस अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक है। सरलता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर, राज्य ने उपभोग में वृद्धि करते हुए अनुपालन को सुदृढ़ किया है।

2025 में, भारत में कर प्रणाली अब नियंत्रण का माध्यम नहीं रह गई है। यह एक साझेदारी है, जो यह मानती है कि जब नागरिकों पर भरोसा किया जाता है और प्रणालियां सरल होती हैं, तो अर्थव्यवस्था विकास के साथ मिलकर कदम बढ़ाती है।

आज का राशिफल

मेषः मेष : धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। सुख-आनंद कारक समय है। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। बुद्धितत्व की सक्रियता से अल्प लाभ का हर्ष होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए भाग-दौड़ रहेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होंगी। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः वृष : घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। बढ़ते घाटे से कुछ राहत मिलने लगेगी। हाथ में आने वाला धन भी किसी अवरोध का शिकार हो जाएगा। व्यापार में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः चापलूस मित्रों से सावधानी रखें तो ज्यादा उत्तम है। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। शत्रुभय, चिंता, संतान को कष्ट, अपव्यय के कारण बनेंगे। संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। सब्र का फल मीठा होता है, अतः धैर्य रखें व अच्छे समय इन्तजार करें। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः थोड़े प्रयास से कार्य सिद्ध होंगे। घर-परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न होने से वातावरण आनन्द देने वाला बना रहेगा। बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा। सुबह-सुबह की महत्वपूर्ण सिद्धि के बाद दिन-भर उत्साह बना रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी। कुछ प्रतिकूल गोचर का क्षोभ दिन-भर रहेगा। माहौल आडंबरपूर्ण और व्ययकारी होगा। वरिष्ठ लोगों से कहासुनी वातावरण में तनाव पैदा करेंगे। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। आवेग में आकर किये गए कार्यों का म्लान, अवसाद रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। कई प्रकार के हर्ष उल्लास के बीच अप्रत्याशित लाभ होंगे। आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने हित के काम सुबह-सवेरे निपटा लें। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः पत्नी व संतान पक्ष से थोड़ी ङूषचता रहेगी। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। बुरी संगति से बचें। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना। *(सिटी दर्पण)*

धनुः शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें। संतान पक्ष की समस्या समाप्त होगी। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। खान-पान में सावधानी रख। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। *(सिटी दर्पण)*

मकरः रुपये पैसों की सुविधा नहीं मिल पाएगी। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर बना रहेगा। यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। *(सिटी दर्पण)*

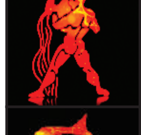
कुंभः आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नवीन जिम्मेदारी बढने के आसार रहेंगे। यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम को प्राथमिकता से करें। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते है। *(सिटी दर्पण)*

मीनः महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते हैं। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। *(सिटी दर्पण)*

हिंदुओं और भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों में कैसे भरा जा रहा है जहर

श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किए जाने और विवेक रामास्वामी के 26 दिसंबर, 2024 को एक्स पर पोस्ट करने के बाद, जब वे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) के लीडर के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल में थे, तो प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी नफरत में काफी बढ़ोतरी देखी गई। जनवरी 2025 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने पर भारत विरोधी नस्लवाद पर एक रिपोर्ट जारी की। तब से, इस बात का कोई खास संकेत नहीं मिला है कि एक्स सहित सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पूर्वाग्रह कम हुआ है। इस रिपोर्ट में एक्स पर भारत विरोधी नस्लवाद के मौजूदा स्तर का विश्लेषण किया गया है। यह भारत विरोधी भावना में बढ़ोतरी का विश्लेषण करती है, भारत विरोधी नस्लवादी बातचीत में मुख्य विषयों और कहानियों को बताती है और उन पोस्ट और मुद्दों पर प्रकाश डालती है जिनका उल्लेखनीय प्रभाव और पहुंच रही है।

एक्स पर 680 ज्यादा एंगेजमेंट वाली भारत विरोधी नस्लवादी पोस्ट को 1 जुलाई से 7 सितंबर, 2025 के बीच 281.2 मिलियन व्यूज मिले। भारतीयों को 'हमलावर' और 'नौकरी चोर' बताने वाली कहानियों के साथ-साथ भारतीयों को देश से निकालने की मांगों वाली 474 पोस्ट (69.7%) और 111.8 मिलियन व्यूज मिले, जिससे इमिग्रेशन और निष्कासन से जुड़ी बातें एंगेजमेंट का मुख्य कारण बन गईं।ल्इ असंतोष और नौकरी चोरी की बातें मुख्य समूह में प्रमुख थीं, जोजेनोफोबिया को आर्थिक असुरक्षा के साथ मिला रही थीं और भारतीयों पर वीजाप्रतिबंध, इनकार, निर्वासन और नागरिकता रद्द करने की मांगों को बढ़ा रही थीं। 121 पोस्ट (17.8%) में भारत विरोधी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें 74.3 मिलियन व्यूज मिले।

12 अगस्त को फ्लोरिडा में एक सिख ड्राइवर से जुड़े ट्रक दुर्घटना संबंधी 74 पोस्ट (10.9%) को 94.9 मिलियन व्यूज मिले, जिससे पता चलता है कि कैसे एक ही घटना का इस्तेमाल पूरे समुदाय को पेशे के आधार पर बलि का बकरा बनाकर बदनाम करने के लिए किया जाता है।

अगस्त 2025 में गतिविधि चरम पर थी, जिसमें 381 पोस्ट और 189.9 मिलियन व्यूज थे। अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद और घटना-आधारित गुस्सा कहानियों में बढ़ोतरी के साथ मेल खाता था, जो दर्शाता है कि नीतिगत तनाव और ब्रेकिंग न्यूज नस्लवादी सामग्री को बढ़ाने वाले अनुमानित कारक के रूप में काम करते हैं। लगभग 65% पोस्ट यूएस पर केंद्रित थे, जिससे यह कन्फर्म होता है कि स्टडी के दौरान यूएस ही भारत विरोधी डिजिटल नस्लवाद का केंद्र था।

हिंदुओं और भारत के प्रति इतनी नफरत क्यों?

असल में, वे भारत से नफरत नहीं करते बल्कि यह एक औपनिवेशिक मानसिकता और विकासशील देशों के प्रति पूर्वाग्रह है। यह उनके प्रभुत्व और भारत के अपनी पुरानी शान में लौटने के लिए खतरा पैदा करता है। पश्चिमी मीडिया और सत्ता संरचनाओं में कई लोगों के लिए भारत सिर्फ. हिंसा, पूर्वाग्रह, गरीबी और सामाजिक अशांति का प्रतीक हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक सोच वाले भारतीय बुद्धिजीवी भी ऐसे ही हैं।

हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी नफरत कई अलग-अलग रूप ले सकती है, जानबूझकर और अनजाने में भी। उदाहरण के लिए, छठी कक्षा के छात्र को मूर्ति पूजक कहा जा सकता है और उसे अपनी क्लास से अलग-थलग महसूस कराया जा सकता है; एक दक्षिण एशियाई प्रोफेसर एक कॉलेज छात्र को हिंदू विरासत का छात्र होने के लिए निशाना बना सकता है और उसे शर्मिंदा कर सकता है; एक चुने हुए अधिकारी पर अमेरिका-भारत संबंधों पर उसकी स्थिति के कारण दोहरी वफादारी का आरोप लगाया जा सकता है और उसके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा सकता है या एक हिंदू अमेरिकी को उसी कारण से नाजी समर्थक कहा जा सकता है।

यह कोई आलोचना नहीं है। सैन्य स्टील्थ हथियारों की तरह, यह एक बेहद घातक, नरसंहार करने वाला

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल (हि.स)

मनोवैज्ञानिक हथियार है जो सबकुछ नष्ट कर देता है। यह जानबूझकर किया गया प्रयास है ताकि दूसरों को भारत के खिलाफ निष्क्रिय या आक्रामक तरीके से लामबंद होने के लिए उकसाया जा सके, उन्हें भारत पर आक्रमण और भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ नस्ली सफाई के लिए तैयार किया जा सके। लक्ष्य भारतीयों को बड़े पैमाने पर और गंभीर रूप से नीचा दिखाना है, ठीक वैसे ही जैसे नाजी जर्मनी और यूरोप के अन्य हिस्सों में यहूदियों के साथ किया गया था, ताकि कई लोग भारतीयों के खिलाफ भी नरसंहार करने की इच्छा रखें। फॉर्मूला वही है। हर बार जब भारतीयों या हिंदुओं को नस्ली सफाई या नरसंहार का शिकार बनाया जाता है, तो उनकी आसानी से उपलब्ध नफरत की कहानी उत्प्रेरक का काम करती है। हर बार जब ये हिंदू विरोधी नरसंहार और जातीय सफाई होती है, तो पश्चिमी मीडिया और संबंधित अकादमिक प्रचारक अपराधों को मिटाने, नकारने और पूरी तरह से सफाई देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि मारे गए हिंदुओं को अपराधी के रूप में पेश करते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उनके इरादे हिंदू विरोधी हैं और वे इसमें शामिल हैं।

इसके अलावा, उनका नैरेटिव लगातार हिंदू समुदाय के खिलाफ घटिया, बदनाम करने वाले और आपस में बांटने वाला प्रोपेगेंडा है, जिसमें भारतीय संस्कृति और क्षेत्रों के सभी लोगों के खिलाफ गंभीर सैन्य, भू-राजनीतिक और नस्लवादी इरादे शामिल हैं। हमेशा की तरह, वे भारत में तबाही, गहरे बंटवारे, दंगे, अंदरूनी कलह, गृह युद्ध, बड़े पैमाने पर विनाश और आत्म-विनाश फैलाने की काली साज़िश के हिस्से के रूप में चुनिंदा, सनसनीखेज कहानी पेश करते हैं। धर्म, अधर्म, धार्मिक गुट, गहरे या हल्के रंग की त्वचा, भाषा, क्षेत्रवाद, राजनीतिक विचारधाराएं, जाति, लिंग, ऐतिहासिक और आर्थिक असमानताएं, पेशे, इतिहास का अकादमिक हेरफेर, आनुवंशिकी, पुरातत्व, और आर्यनआक्रमणसिद्धांत का अकादमिक हेरफेर। जब तक यह भारतीयों या पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी भड़का सकता है, वे अपने पास मौजूद हर हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। उनकी खास रणनीति फूट डालना और अंदरूनी कलह पैदा करना है। बांटो और राज करो एक पुराना लेकिन बेतुके रूप से असरदार तरीका है। इसका इस्तेमाल अभी भी भारतीयों के बीच आत्म-विनाश और गृहयुद्ध भड़काने के लिए किया जा रहा है।

'गौमूत्र' के ताने भारतीय इस्लामी-वामपंथी माहौल में आम हो गए हैं। 'अमेरिका फर्स्ट' एक्टिविस्ट के रूप में खुद को छिपाने वाले अमेरिकी ईसाई श्रेष्ठतावादी अब एक बहस में हिंदुओं के खिलाफ उसी गाय के पेशाब और गोबर के ताने इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्च 2024 का होने के बावजूद एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हिंदुओं से नफरत करने वाला स्टू पीटर्स, जो भारत को बहुत अच्छी तरह से जानने का झूठा दावा करता है, भारतीयों को 'बिंदी वाले तिलचट्टे और परजीवी' कह रहा है। वीडियो में, पीटर्स दावा करता है कि भारतीय अपने चेहरों पर गोबर लगाते हैं और उससे अपने दांत साफ करते हैं। साथ ही और भी कई झूठी बातें कहता है जो एक आम नस्लवादी जो भारत से नफरत करता है, अलग-अलग घटनाओं की रिपोर्ट के आधार पर गढ़ सकता है और उसे पूरे भारत की घटना के रूप में पेश कर सकता है, जैसे कि अमेरिका में ईसाई बहुमत एक (काल्पनिक) आदर्श जगह है या अगर 'बिंदी वाले' हिंदू भारतीयों को खत्म कर दिया जाए तो वह बन जाएगी। यह वही अमेरिका है जिसके व्यवसायों ने गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं बनाने के लिए गोमूत्र के पेटेंट का इस्तेमाल किया। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए गायों का इस्तेमाल करने वाले अमेरिकी भी वही लोग हैं।

प्यू रिसर्च सेंटर के एक एनालिसिस के अनुसार, दुनिया भर में सभी प्रवासियों में 47% ईसाई है, उसके बाद मुस्लिम (29%), हिंदू (5%), बौद्ध (4%), और यहूदी (1%) है। दुनिया के 1 अरब हिंदुओं में से सिर्फ 5% विदेशी प्रवासी हैं। प्यू रिसर्चर स्टेफनी क्रैमर के अनुसार, इसका कारण यह है कि 'हिंदू भारत में बहुत ज्यादा केंद्रित हैं और भारत में पैदा हुए लोगों के देश छोड़ने की संभावना बहुत कम है।'

हिंदू धर्म के विपरीत, पश्चिमी बुद्धिजीवी भारत के उदय से डरने के बजाय उससे नाराज हैं। भारत की समृद्धि पश्चिमी हिंदू विरोधी लोगों को परेशान करती है, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल की सफलता पश्चिमी यहूदी विरोधी लोगों को परेशान करती है। हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी वाले एक शक्तिशाली, स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा उनके लिए अस्वीकार्य है। जैसा कि उनके पूर्वजों ने सदियों पहले किया था, वे भारत को कमजोर और गरीब रखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसलिए, पश्चिमी हिंदू विरोधी लोगों के उद्देश्य कई भारतीय बुद्धिजीवियों के साथ-साथ भारत विरोधी इस्लामवादियों के उद्देश्यों से भी मिलते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि भारतीय बुद्धिजीवी भारत विरोधी या हिंदू विरोधी हैं। इसका कारण यह है कि कई भारतीय बुद्धिजीवी उस धर्मनिरपेक्ष, कम्युनिस्ट और कमजोर भारत की कामना करते हैं जो हिंदू विरोधी लोग चाहते हैं।

यह भी मजेदार है कि ईसाई वर्चस्ववादी इस बात पर जोर-शोर से शिकायत करते हैं कि हिंदू उनकी नौकरियाँ, जमीन और दूसरी चीजों पर 'कब्जा कर रहे हैं', जबकि वे अमेरिकी ईसाई मिशनरियों के बारे में चुप रहते हैं जो टूरिस्ट वीजा पर भारत में घुसते हैं और वित्तीय प्रलोभन और चमत्कारिक रूप से बीमारियों को ठीक करने के बहाने हिंदुओं, सिखों, आदिवासी लोगों और अन्य समुदायों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करते हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पंजाब शिक्षा क्रांति: पेस विंटर कैंपों में सरकारी स्कूलों के 1700 से अधिक विद्यार्थियों को आईआईटी, एनआईटी, एम्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दी गई तैयारी

कैंपों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को देश की शीर्ष संस्थाओं—आईआईटी, एनआईटी और एम्स—के लिए तैयार करना: हरजोत सिंह बैंस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने आज यहां बताया कि पंजाब अकादमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस (पेस) कार्यक्रम के तहत आयोजित विंटर रेज़िडेंशियल कोचिंग कैंपों में पंजाब के सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की गई। इस कार्यक्रम से 1700 से अधिक विद्यार्थियों ने लाभ उठाया, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च-स्तरीय कोचिंग तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

स. बैंस ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भारत की शीर्ष पेशेवर शैक्षणिक संस्थाओं जैसे आईआईटी, एनआईटी और एम्स के लिए तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित इन कैंपों के तीन केंद्रों में कुल 1728 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें बठिंडा में 601 विद्यार्थी (359 छात्राएं, 242 छात्र), लुधियाना में 573 विद्यार्थी (327 छात्राएं, 246 छात्र) और एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में 554 विद्यार्थी (367 छात्राएं, 187 छात्र) शामिल थे।

उन्होंने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उस दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसके तहत सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा और करियर मार्गदर्शन के समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, ह्लपेस विंटर कैंपों को मिला उत्साहपूर्ण प्रतिसाद हमारे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अपार क्षमताओं को दशार्ता है। यह पहल युवाओं को सशक्त बनाती है, उनमें आत्मविश्वास पैदा करती है और किसी भी पृष्ठभूमि के योग्य विद्यार्थियों को शीर्ष संस्थानों में पढ़ने का निष्पक्ष अवसर देती है। हम ऐसा शैक्षणिक वातावरण बना रहे हैं जो उत्कृष्टता और समानता को प्राथमिकता देता है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये शीतकालीन कैंप विभाग द्वारा चलाई जा रही व्यापक पहलों में से एक हैं, जिनमें विद्यार्थियों के चयन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई गई। चयन प्रक्रिया में मॉक टेस्ट, अवधारणात्मक स्पष्टता, अकादमिक निरंतरता और शिक्षकों की सिफारिशों के आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि समावेशी दृष्टिकोण के तहत प्रत्येक केंद्र में 20 प्रतिशत सीटें सामान्य सरकारी स्कूलों और ड्रॉप-ईयर अभ्यर्थियों के लिए

आरक्षित रखी गईं, जिससे स्कूल ऑफ एमिनेंस और रेज़िडेंशियल स्कूलों के अलावा अन्य मेधावी विद्यार्थियों को भी इस पहल का लाभ मिल सके।

स. बैंस ने कहा कि इन कैंपों ने विद्यार्थियों को व्यापक शिक्षण अनुभव प्रदान किया, जहां फिजिक्सवाला, विद्या मंदिर और अवंती फेलोज जैसी शीर्ष कोचिंग संस्थाओं के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। पाठ्यक्रम जेईई और नीट पैटर्न के अनुरूप अवधारणात्मक स्पष्टता और उन्नत समस्या-समाधान पर केंद्रित था। इसके अतिरिक्त, दैनिक डाउट-क्लियरिंग सत्र, वन-टू-वन मेंटरिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, करियर मार्गदर्शन और मनोरंजक गतिविधियों पर आधारित मॉड्यूल्स ने विद्यार्थियों की समग्र भलाई सुनिश्चित की। बेहतर और सुरक्षित आवासीय सुविधाओं ने अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया।

उन्होंने विश्वास जताया कि ये शीतकालीन रेज़िडेंशियल कोचिंग कैंप 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रशिक्षण देकर प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाएंगे और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 265 सरकारी स्कूल विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स, 45 ने जेईई एडवांस्ड और 847 ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे स्पष्ट है कि राज्य के सरकारी स्कूल अब देश के शीर्ष पेशेवर करियर पाठ्यक्रमों के लिए लॉन्चपैड के रूप में उभर रहे हैं।

पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से ह्लपेसह्व कार्यक्रम के तहत विंटर रेज़िडेंशियल कोचिंग कैंपों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशासनिक और अकादमिक व्यवस्थाएं कीं। लुधियाना, बठिंडा और मोहाली में स्थापित तीन आवासीय केंद्रों में ये कैंप आयोजित किए गए, जिनमें मानकीकृत अकादमिक योजना, पूर्ण निगरानी और सभी केंद्रों पर एकसमान सिलेबस डिलीवरी सुनिश्चित की गई।

निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रत्येक केंद्र में अन्य सरकारी स्कूलों और ड्रॉप-ईयर अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गईं, ताकि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस रेज़िडेंशियल स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इस पहल का लाभ मिल सके।

पंजाब सरकार ने रिहायशी कैंपों में संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की थी ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मुहैया करवाया जा सके। विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, 24 घंटे निगरानी, चिकित्सा और काउंसलिंग सहायता जैसी संपूर्ण व्यवस्थाएं कीं, जिससे वे पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन कर सकें। नामी कोचिंग संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से अकादमिक प्रशिक्षण के साथ-साथ दैनिक शंका-निवारण सत्र, संरचित मेंटरशिप, तनाव प्रबंधन और करियर मार्गदर्शन पर केंद्रित समग्र मॉड्यूल प्रदान किए गए। ये प्रबंध आईआईटी, एनआईटी, एम्स और अन्य प्रमुख संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ तैयार करने की दिशा में पंजाब सरकार के उत्कृष्टता, समानता और विद्यार्थी कल्याण केंद्रित प्रयासों को दशार्ते हैं।

मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में सरकार द्वारा व्यापारी-अनुकूल शासन को मजबूत करने के लिए एकमुश्त निपटारा योजना में मार्च 2026 तक विस्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- **पंजाब सरकार द्वारा व्यापारियों एवं उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए कर बकाये के लिए ह्यएकमुश्त निपटारा योजना-2025ह्न में 31 मार्च तक विस्तार: हरपाल सिंह चीमा**
- **6,300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, उद्योग की मांग एवं कर पालना को आसान बनाने के लिए दिया गया विस्तार**

राज्य के व्यापारी समुदाय एवं उद्योग को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ह्यबकाया करों की रिकवरी संबंधी पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना, 2025ह्न की समय-सीमा 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जी.एस.टी. प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (जी.एस.टी.पी.ए.), पंजाब सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई अपील के बाद इस विस्तार के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी। यह निर्णय अब तक इस योजना को मिले समर्थन के मद्देनजर भी लिया गया है, जिसके तहत कर विभाग को आज तक 6,348 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 के अंतिम महीनों के दौरान विभिन्न टैक्स रिटर्न भरने की तिथियाँ एक साथ आने के कारण करदाताओं पर काम का काफी बोझ था। इसके अलावा, वैट असेसमेंट ऑर्डर्स की लंबित डिलीवरी जैसी व्यावहारिक चुनौतियों के कारण कई व्यापारियों के लिए दिसंबर की मूल समय सीमा से पहले अपनी देनदारियों का सही निर्धारण करना कठिन हो रहा था।

ओ.टी.एस. स्कीम-2025, जो पहली अक्टूबर से शुरू की गई थी, राज्य की सबसे बड़ी करदाता-अनुकूल पहल साबित हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने कानूनी विवादों को समाप्त करना तथा सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। निर्धारित मांग की राशि के आधार पर, करदाता ब्याज एवं जुमार्ने पर 100 प्रतिशत तक की छूट के साथ-साथ मूल टैक्स की राशि पर भी बड़ी राहत प्राप्त कर सकते हैं।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि समय सीमा में यह विस्तार ईमानदार करदाताओं के लिए जीएसटी से पूर्व के अधिनियमों (वैट एवं केंद्रीय विक्रय कर सहित) के तहत लंबे समय से लंबित विवादों को बिना किसी मानसिक दबाव के निपटाने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। वित्त मंत्री ने आगे कहा, ह्यहमारी सरकार व्यापार अनुकूल माहौल सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय सीमा को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी योग्य करदाता प्रशासनिक या समय की कमी के कारण इस लाभ से वंचित न रहे।ह्नह्न

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी योग्य व्यापारियों एवं राइस मिलरों से अपील की कि वे अपने बकाये साफ करने के लिए इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएँ तथा नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत बिना किसी बोझ के करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 की नई समय सीमा के बाद, विभाग द्वारा उन डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त वसूली कार्रवाई शुरू की जाएगी जो इस निपटारा योजना का अवसर नहीं चुनेंगे।

हरियाणा से आ रही पिकअप गाड़ी से बड़ी मात्रा में पाबंदी सुदा कीटनाशक बरामद, केस दर्ज

सिटी दर्पण संवाददाता
बठिंडा

मुख्य कृषि अधिकारी बठिंडा डॉ. हरबंस सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण विभाग बठिंडा की क्वालिटी कंट्रोल के लिए बनाई गई जिला स्तरीय टीम ने एक खास चैकिंग अभियान के तहत जिले में रामां मंडी के पास गांधी चौक पर कालांवाली (हरियाणा) से आ रहे एक महिंद्रा पिक-अप गाड़ी को रोका और चैक किया। चैकिंग के दौरान गाड़ी से बड़ी मात्रा में पाबंदी सुदा कीटनाशक अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71% एसजी और 41% एसएल (राउंडअप) बरामद किया गया, जिससे समाज में कैंसर जैसी अनचाही बीमारियां होती हैं और जमीन बंजर हो जाती है। उक्त कीटनाशक बरामद करने के बाद टीम ने कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई की और सैंपल लिए और उसके बाद संबंधित खरपतवार नाशक पुलिस को सौंप दिया गया और ऋक्रफ़ दर्ज की गई। इस कीटनाशक के संबंध में कीटनाशक अधिनियम और नियमों के

अनुसार उचित कार्रवाई की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण विभाग, बठिंडा ने किसानों से इस खरपतवार नाशक का इस्तेमाल न करने की अपील की। उन्होंने खरपतवार नाशक बेचने वालों से भी इस खरपतवार नाशक को न बेचने की अपील की, नहीं तो विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। चैकिंग टीम में टीम इंचार्ज के तौर पर डॉ. दविंदर सिंह संधू, सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी बठिंडा और डॉ. मनदीप सिंह एडीओ (पीपी) बठिंडा, डॉ. गुरकंवल सिंह एडीओ (पीपी) तलवंडी साबो, श्री गुरदीप सिंह बेलदार बठिंडा और श्री बलकौर सिंह बेलदार तलवंडी साबो आदि शामिल थे।

संक्षिप्त-समाचार

स्पीकर द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर पुनर्विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

चंडीगढ़ । पंजाब विधान सभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा माइनिंग रेगुलेशन कमेटी की सिफारिशों पर अगले आदेशों तक रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। स्पीकर संधवां ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कमेटी द्वारा सिफारिश की गई अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इससे संबंधित गंभीर शंकाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया है और पिछले आदेशों पर रोक लगा दी है। स्पीकर ने कहा कि व्यावसायिक उद्देश्यों की बजाय पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अरावली पहाड़ियों की ह्यपरिभाषाह्न में बदलाव के कारण यह विवाद पैदा हुआ है। नई परिभाषा के अनुसार, केवल वही क्षेत्र पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर अधिक हो। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इस परिभाषा से अरावली क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत छोटी पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकती हैं, जिससे वहां माइनिंग और रियल एस्टेट गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अरावली पहाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, तो रेगिस्तान से आने वाली हवाएं दिल्ली-एन.सी.आर. की ओर बहेंगी। ये पहाड़ियां ह्यग्रीन वॉलह्न की तरह काम करती हैं जो रेत और धूल को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन पहाड़ियों को खत्म करने से उत्तरी भारत में धूल भरे तूफान और वायु प्रदूषण का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। स्पीकर ने कहा कि अरावली पहाड़ियों के नुकसान से किसी एक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी भारत के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अरावली पहाड़ियों की प्रभावी एवं टिकाऊ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उपयुक्त और स्थायी कदम उठाए जाने चाहिए।

फिरोजपुर रेल मंडल में ट्रेनों के टाइमटेबल में बदलाव: परमजीत सिंह सैनी

जैतो। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर परमजीत सिंह सैनी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारतीय रेलवे हर साल यात्रियों की सुविधा बेहतर बनाने, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और ऑपरेशन को ज्यादा कुशल बनाने के मकसद से ट्रेनों के टाइमटेबल में जरूरी बदलाव करता है। इसी सिलसिले में, फिरोजपुर डिवीजन के तहत चलने वाली ट्रेनों के टाइमटेबल में 1 जनवरी, 2026 से कुछ बदलाव किए गए हैं। टाइमटेबल में ये बदलाव यात्रियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, यात्रा का समय कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए सुधारों का फायदा उठाने के लिए किए गए हैं। इसका मकसद ट्रेनों की समय की पाबंदी सुनिश्चित करना और उनके गंतव्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ट्रेनों के लेटेस्ट टाइमटेबल भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम और रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर उपलब्ध हैं। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर श्री परमदीप सिंह सैनी ने रेलवे यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ट्रेनों का टाइमटेबल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर देख लें।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 स्कीम लॉन्च: डीसी राजेश धीमान

बठिंडा। डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश धीमान ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 स्कीम लॉन्च की गई है, जो 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को मदद देती है, जिनके पास अभी गैस कनेक्शन नहीं है। यह स्कीम 31 मार्च, 2026 तक है। इस पहल का मकसद प्रदूषण कम करना, खाना पकाने के लिए साफ ईंधन तक पहुँच देना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए, ज़िला कंट्रोलर और सप्लाई अधिकारी दलजीत सिंह संधू ने कहा कि इस फायदे को पाने के लिए, एक गरीब परिवार की वयस्क महिला जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, उसे एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए योग्य होने के लिए, परिवार के सदस्यों का दस्तावेज (राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड के अनुसार) किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर मौजूदा एल.जी.पी. कनेक्शन रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार के सदस्य की आय प्रति माह 10 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं देता हो, 50 हजार से ज्यादा की लिमिट वाला कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, घर का कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई 3/4 पहिया वाहन या खेती का उपकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए, कोई भी पास की गैस एजेंसी या वेबसाइट ख़४८.ङ्म५.ल्ल पर देख सकता है।

डीसी फरीदकोट पूनमदीप कौर ने जिले के निवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दीं

जैतो। डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर ने नए साल 2026 के आगमन के अवसर पर फरीदकोट जिले के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें, नया उत्साह और नई उपलब्धियां लेकर आए। उन्होंने कहा कि नया साल हमें पिछले अनुभवों से सीखने और भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विकास कार्यों को और गति देने, जमीनी स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और नागरिकों के हर वर्ग तक सरकारी सेवाओं की सुचारू पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आइए हम सब मिलकर आपसी भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, शांति और सौहार्द को मजबूत करने के लिए काम करें ताकि फरीदकोट जिला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में नए मानक स्थापित कर सके। अंत में, उन्होंने कामना की कि नया साल हर नागरिक के जीवन में शांति, स्वास्थ्य, प्रगति, समृद्धि और खुशियां लाए और फरीदकोट जिला निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

सर्वधर्म बेअदबी रोको टावर मोर्चा समाना से श्री अमृतसर साहिब तक शुरू हुई पैदल यात्रा का हिस्सा बने किसान : लखविंदर सिंह औलख

जैतो। बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने टावर मोर्चा समाना से जानकारी देते हुए बताया कि 12 अक्टूबर 2024 से सर्वधर्म बेअदबी रोको कानून बनवाने के लिए समाना (पंजाब) में टावर मोर्चा लगा हुआ है, जिसमें वीरवार को किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कोटबुढा व भारतीय किसान एकता बीकेई ने भी अपनी हाजिरी लगवाई। औलख ने कहा कि भाई गुरजीत सिंह खालसा 400 फीट ऊंचे टावर पर 4*6 फीट की जगह में

पिछले 448 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। गुरजीत सिंह खालसा की कई बार तबीयत भी नाजुक हो गई थी, टावर मोर्चा की कमेटी व समूह साथ संगत के सहयोग से परसों रोज से चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब के आज भोग डाले गए। तत्पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में नगर कीर्तन के साथ पैदल यात्रा शुरू कि गई, जो 15 जनवरी 2026 को श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहिब पहुंचेगी। पैदल श्रद्धालुओं के लिए रात्रि पड़ाव का शेड्यूल भी जारी किया गया है। औलख ने शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आस्था रखने वाले सभी धर्म प्रेमियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा का हिस्सा बनें। सभी इकट्ठे होकर दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब अरदास करें कि वाहेगुरु सरकारों को सद्बुद्धि बक्शे। सर्वधर्म बेअदबी रोको सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सहित सभी धार्मिक ग्रंथों की हो रही बेअदबी को रोका जा सके। इस मौके पर त्रिलोक सिंह, अमरीक सिंह, साहब सिंह, अंग्रेज सिंह कोटली, जीत सिंह, दिलबाग सिंह, गुरप्रीत संधू, दलजीत सिंह विर्क, सुखवंत सिंह, भूपेंद्र सिंह, तेजा सिंह, नरेंद्र सिंह, बापू हरचरण सिंह, बलवंत सिंह, हरदीप सिंह, मुकेश सिंह, हरपाल सिंह, सतपाल सिंह, करमजीत सिंह, बलदेव सिंह, तारा सिंह, गुरजीत मान, राजू फूलकां आदि मौजूद रहे।

कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ए.आई. का उपयोग करेगा पंजाब

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आधुनिक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा आई.आई.टी. रोपड़ में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की सहायता से कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने यहां पंजाब भवन में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कृषि सेक्टर की प्रगति का जायजा लेने के साथ-साथ कृषि उत्पादन एवं टिकाऊ विकास में वृद्धि तथा राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एआई-आधारित समाधानों को प्रभावी ढंग से अपनाने संबंधी रोडमैप तैयार करने पर चर्चा की गई।

स. खुड्डियां ने जोर देकर कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों को ठोस सहायता एवं उचित लाभ प्रदान करने को

सुनिश्चित बनाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करना समय की जरूरत है। उन्होंने इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट लागू करने तथा जिलों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऑटोमैटिक वेदर (मौसम) स्टेशनों की स्थापना, फील्ड डेटा एकत्र करने के लिए किसानों की भागीदारी, बागबानी क्लस्टरों को सहायता तथा एआई-आधारित पशुधन उत्पादकता समाधानों के विस्तार को सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए।

कृषि मंत्री ने आईआईटी रोपड़ द्वारा कृषि सेक्टर में कृषि की सही तकनीकों एवं एआई के उचित उपयोग संबंधी नेशनल-लेवल के कोर्स शुरू करने की पहलकदमी का भी स्वागत किया, जिसका उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास एवं सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है। पंजाब के विद्यार्थियों एवं अधिकारियों के लिए सीटों का विशेष आरक्षण कृषि-तकनीक में राज्य के मानव संसाधन आधार को और मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि यह सहयोग पंजाब को एआई-आधारित कृषि सुधारों के क्षेत्र में एक अग्रणी एवं मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों से कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में संसाधन कुशलता, जलवायु-अनुकूलता एवं टिकाऊ विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान आईआईटी, रोपड़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पुष्पेंद्र पी सिंह ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, के अंतर्गत मुख्य पहलकदमियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें एआई-आधारित फसल सलाहकार प्रणालियां, बहु-भाषाई किसान चैटबॉट्स, फसलों के डिजिटल ट्विन्स, उपज अनुमान मॉडल, मिट्टी स्वास्थ्य विश्लेषण, मौसम इंटेलिजेंस टूल एवं स्मार्ट पशुधन प्रबंधन एप्लीकेशन्स शामिल हैं।

इस बैठक में कृषि विभाग के सचिव श्री अर्शदीप सिंह थिंद, एमडी पंजाब एग्रो हरगुंजीत कौर, डायरेक्टर कृषि विभाग जसवंत सिंह, डायरेक्टर पशुपालन परमदीप सिंह वालिया एवं राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

हमारी सरकार अनुशासनहीनता एवं ड्यूटी में लापरवाही के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति बनाए रखती है: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार द्वारा लंबे समय से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए आबकारी एवं कर विभाग के 4 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- **हम पंजाब के लोगों के लिए पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध: हरपाल सिंह चीमा**
- **स्टेट टैक्स कमिश्नर द्वारा एक साल से अधिक समय से अनुपस्थित चार अधिकारियों के विरुद्ध ह्यडीम्ड इस्तीफा नियमह्न लागू**

सख्त अनुशासन एवं जवाबदेही लागू करने के लिए पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा के निदेर्शों की पालना करते हुए स्टेट टैक्स कमिश्नर, पंजाब ने एक साल से अधिक समय से अनधिकृत छुट्टी पर पाए गए चार विभागीय कर्मचारियों के ह्यडीम्ड इस्तीफेह्न के आदेश जारी किए हैं। स्टेट टैक्स कमिश्नर जतिंदर जोरवाल द्वारा जारी किए गए ये आदेश तीन आबकारी एवं कर इंस्पेक्टरों एवं एक क्लर्क पर लागू होते हैं, जो कई कानूनी नोटिसों एवं अपने संबंधित कार्यालयों में पुनः हाजिर होने का मौका दिए जाने के बावजूद अपनी ड्यूटियों से अनुपस्थित रहे।

इस अनुशासनात्मक कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ह्यहमारी सरकार अनुशासनहीनता एवं ड्यूटी में लापरवाही के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति रखती है। जनसेवा के लिए समर्पण एवं उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए, वे कर्मचारी जिन्हें बार-बार अपनी स्थिति स्पष्ट करने के मौके दिए जाते हैं लेकिन वे लगातार वर्षों से अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, उनके लिए प्रशासन में कोई स्थान नहीं है। हम पंजाब के लोगों के लिए एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।ह्नह्न

पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम, 1970 के नियम 8 के तहत की गई एक सख्त जाँच प्रक्रिया के

बाद इन 4 कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त की गई हैं। इस मामले में एक इंस्पेक्टर अपनी छुट्टी की अर्जी उच्च अधिकारियों द्वारा रद्द किए जाने के बाद 15 मार्च, 2023 से जालंधर-2 में अपने पद से अनुपस्थित था। इसी तरह, एक अन्य इंस्पेक्टर 24 जून, 2023 से लगातार अनुपस्थित पाया गया। वह निलंबित किए जाने के बावजूद अपने निर्धारित मुख्यालय को संतोषजनक स्पष्टीकरण या रिपोर्ट देने में असफल रहा।

विभाग द्वारा रोपड़ रेंज के एक इंस्पेक्टर के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, जो अपनी मंजूरशुदा एक्स-इंडिया छुट्टी की समाप्ति के बाद 29 मई, 2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित था। इस कर्मचारी द्वारा स्वास्थ्य संबंधी एवं हृदय सर्जरी के दावों के बावजूद, स्वतंत्र जाँचों में उसे अपनी सरकारी ड्यूटियों में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाया गया क्योंकि वह वर्चुअल मोडों के द्वारा भी जाँच में शामिल होने में असफल रहा। इसके अलावा, जालंधर ऑडिट विंग का एक क्लर्क द्वारा एक्स-इंडिया छुट्टी की मंजूरी न मिलने के बाद 11 सितंबर, 2023 से ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहने के बाद उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।

इन चारों मामलों में, आबकारी एवं कर विभाग ने 13 मार्च, 2025 की वित्त विभाग की हिदायतों के अनुसार ह्यडीम्ड इस्तीफाह्न धारा का उपयोग किया। इस नियम के तहत एक साल से अधिक समय के लिए मंजूरशुदा छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहने वाले किसी भी कर्मचारी को सरकारी सेवा से इस्तीफा दिया हुआ माना जाएगा। इस इस्तीफे के परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों को कोई ग्रेच्युटी, पेंशनरी लाभ, या कोई अन्य सेवा-संबंधित लाभ नहीं दिया जाएगा। इस मामले में सक्षम अधिकारी ने पाया कि जबकि कुछ कर्मचारियों ने पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन वे कानूनी रूप से मंजूर समय सीमा के अंदर ड्यूटी पर पुनः हाजिर होने में असफल रहे, जिस कारण अंतिम प्रशासनिक आदेश जारी किए गए।

पश्चिम बंगाल को मिली पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती

मनोज पंत होंगे मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी

- नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

पश्चिम बंगाल में पहली बार किसी महिला अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने नंदिनी चक्रवर्ती को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बुधवार रात नवान्न से जारी अधिसूचना में इस फैसले की जानकारी दी गई। निवर्तमान मुख्य सचिव मनोज पंत को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है।

नंदिनी चक्रवर्ती इससे पहले गृह, पहाड़ और पर्यटन विभाग की सचिव के पद पर कार्यरत थीं। उनके स्थान पर जगदीश प्रसाद मीणा को राज्य का नया गृह सचिव बनाया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उनकी सेवानिवृत्त जून 2029 के अंत में है। इसका मतलब है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक वही राज्य की मुख्य सचिव होंगी। आज एक जनवरी से मीणा औपचारिक रूप से गृह सचिव का कार्यभार संभालेंगे। मनोज पंत का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाया था, जो 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। ऐसे में नए साल से पहले नए मुख्य सचिव की नियुक्ति जरूरी हो गई थी। इसी क्रम में बुधवार रात प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर नंदिनी चक्रवर्ती की नियुक्ति की घोषणा कर दी। बुधवार को नवान्न में निवर्तमान

फोटोः हि.स.

मुख्य सचिव मनोज पंत ने पुष्पगुच्छ देकर अपनी उत्तराधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को शुभकामनाएं दीं। नंदिनी चक्रवर्ती को 31 दिसंबर, 2023 को राज्य का गृह सचिव बनाया गया था। वह पश्चिम बंगाल की दूसरी महिला गृह सचिव थीं। राज्य की पहली महिला गृह सचिव लीना चक्रवर्ती रही हैं, जो वाम शासन के दौरान इस पद पर थीं। नंदिनी की गृह सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर उस समय राजनीतिक विवाद भी हुआ था। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस नियुक्ति को पूरी तरह अवैध बताते हुए दावा किया था कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज कर नंदिनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सरकारी नियमों में ऐसी नियुक्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं है और यह परंपरा और प्रथा से जुड़ा मामला माना जाता है। संयोग से उसी परंपरा के तहत अब उन्हें मुख्य सचिव भी बनाया गया है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को सुपरसीड किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस प्रशासनिक फैसले को कई लोग व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के तौर पर देख रहे हैं। मनोज पंत को मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर एक अहम जिम्मेदारी में बरकरार रखा गया है। प्रशासन के एक वर्ग का मानना है कि यह मनोज पंत का पदोन्नयन जैसा कदम है। वे पहले की तरह मुख्यमंत्री से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को देखते रहेंगे। इसके साथ ही मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौतम सान्याल की तबीयत खराब चल रही है, ऐसे में उनके काम का बोझ भी कम किया गया है। साथ ही उनके सेवानिवृत्त होने की स्थिति में भविष्य की व्यवस्था भी कर दी गई है।

जगदीश को गृह सचिव बनाए जाने को लेकर भी नवान्न के भीतर चर्चा है। वे राज्य प्रशासन के इतिहास में सबसे जूनियर गृह सचिव माने जा रहे हैं, क्योंकि वे सीधे सचिव पद से गृह सचिव बनाए गए हैं। परंपरागत रूप से इस पद पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होती रही है। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि जूनियर होने के कारण जगदीश को समय-समय पर मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से मार्गदर्शन लेने में कोई असहजता नहीं होगी।

हाजिर चांदी के भाव में मामूली गिरावट

- चेन्नई और हैदराबाद में चांदी अभी भी 2.50 लाख के पार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

साल 2026 के पहले दिन घरेलू सरार्फा बाजार में चांदी के भाव में मामूली कमजोरी दर्ज की गई है। आज इस चमकीली धातु की कीमत में 1,000 रुपये से लेकर 1,400 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। कीमत में आई इस गिरावट के बावजूद चेन्नई और हैदराबाद में ये चमकीली धातु अभी भी ढाई लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर के ऊपर बनी हुई है। देश के अलग अलग सरार्फा बाजारों में आज चांदी 2,38,700 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 2,56,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक के भाव पर बिक रही है।

दिल्ली में आज चांदी 2,38,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसी तरह मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में चांदी 2,38,700 रुपये के भाव पर कारोबार कर रही है। जबकि जयपुर, सूरत और पुणे में चांदी 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। वहीं बेंगलुरु में चांदी 2,39,200 रुपये के स्तर पर और पटना तथा भुवनेश्वर में 2,38,800 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसके अलावा हैदराबाद में चांदी 1,400 रुपये सस्ती होकर 2,56,800 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। देश में चांदी की सबसे अधिक कीमत आज भी चेन्नई में है, जहां ये चमकीली धातु आज 1,400 रुपये कमजोर होकर 2,56,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को चेन्नई में चांदी की कीमत 2,75,000 हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। साल 2025 में चांदी की कीमत में 180 प्रतिशत से भी अधिक की तेजी आ गई थी। लंदन सिल्वर मार्केट में चांदी का हाजिर भाव 83.62 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर शुरू हुई मुनाफा वसूली, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की बढ़ी उपलब्धता और भू-राजनीतिक तनाव में आई कमी की वजह से साल के आखिरी सप्ताह में इस चमकीली धातु की कीमत में गिरावट आनी शुरू हो गई। इसके साथ ही फ्यूचर ट्रेडिंग में सिल्वर फ्यूचर पर मार्जिन बढ़ा दिए जाने की वजह से चांदी पर दबाव की स्थिति बन गई। कैपेक्स गोल्ड एंड इनवेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता के मुताबिक शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने कमोडिटी एक्सचेंज इंक (कॉमेक्स) और दूसरे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स पर मार्जिन में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

सिल्वर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए पहले जहां कारोबारियों को मार्जिन के रूप में जहां लगभग 20 हजार डॉलर देना पड़ता था, वो अब बढ़ कर लगभग 25 हजार डॉलर हो गया है। मार्जिन बढ़ने से कारोबारियों को तुलनात्मक रूप से अधिक राशि का भुगतान करने की मजबूरी बन गई, जिसकी वजह से कई बड़े कारोबारियों ने अपनी पोजिशन काटने के लिए बिकवाली शुरू कर दी। इस बिकवाली ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजापर में चांदी की कीमत पर दबाव बना दिया, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी कीमत में आई गिरावट के रूप में नजर आ रहा है।

सरार्फा बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट

- 1,310 रुपये तक सस्ता हुआ सोना

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

घरेलू सरार्फा बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट का रुख बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट में पिछले लगातार तीन सत्र के दौरान हुई जोरदार मुनाफा वसूली के कारण घरेलू सरार्फा बाजार में भी सोने के भाव में कमजोरी आ गई है। सरार्फा बाजार में आज हाजिर सोना 1,200 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,310 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है।

कीमत में आई इस कमजोरी के कारण देश के ज्यादातर सरार्फा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,34,880 रुपये से लेकर 1,35,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,23,640 रुपये से लेकर 1,23,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह दिल्ली सरार्फा बाजार में आज चांदी 2,38,900 रुपये प्रति किलोग्राम के

फोटोः हि.स.

भाव पर कारोबार कर रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,35,030 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,790 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,23,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,34,930 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,23,640 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,23,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,23,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

लखनऊ के सरार्फा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,35,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,23,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,23,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,35,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,23,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सरार्फा बाजार में भी आज सोने के भाव में गिरावट आई है।

यूक्रेन ने पुतिन को निशाना नहीं बनाया

- अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का दावा

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

अमेरिका की खुफिया संस्था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ने रूस के उस दावे को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के आवास को निशाना बना कर घातक ड्रोन हमला किया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सीआईए ने क्रेमलिन के दावे के बाद सच पता लगाने के लिए यूक्रेन ड्रोन हमले का आकलन किया है। इसमें पता लगा है कि यूक्रेन ने अपने देश के उत्तर में हाल ही में हुए ड्रोन हमले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस्तेमाल किए जाने वाले आवास को निशाना नहीं बनाया था। सीआईए का यह निष्कर्ष सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान रूसी नेता के आरोप को गलत साबित करती है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के

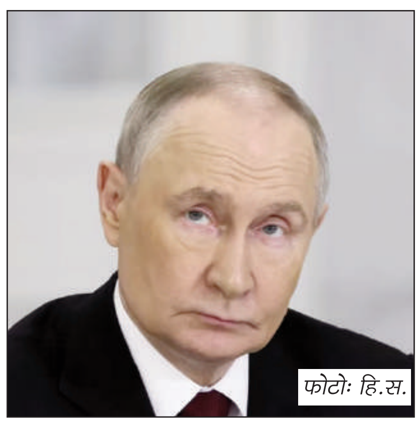
फोटोः हि.स.

अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप को इस आकलन के बारे में जानकारी दी।

उल्लेखनीय है, रूस ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने सोमवार को पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वह यूक्रेन की इस कार्रवाई से परेशान हैं। हालांकि यूक्रेन ने उसकी ओर से ऐसे हमले की बात से इनकार किया था।

सूत्रों ने बताया कि रैटक्लिफ ने ट्रंप को बताया कि सीआईए को रूसी दावे के सच होने पर यकीन नहीं था। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर न्यूयॉर्क पोस्ट के एक संपादकीय का लिंक पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था, पुतिन का उनके आवास पर 'हमले' का दिखावा यह प्रदर्शित करता है और दरअसल रूस ही शांति के रास्ते में रुकावट बन रहा है।

उधर रूसी राष्ट्रपति के मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वह उक्त हमले का फिलहाल कोई सबूत तो नहीं दे सकते हैं। मीडिया को क्रेमलिन की बात पर यकीन करना चाहिए। सीआईए ने पेस्कोव के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है।

संक्षिप्त-समाचार

बांकुड़ा में बेकाबू बोलेरो ने टोटो को मारी टक्कर, दो की मौत

बांकुड़ा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के गंगाजलघाटी थाना अंतर्गत भैरवपुर गांव में एक बेकाबू बोलेरो ने पहले एक टोटो को टक्कर मारी और फिर एक राहगीर को कुचल दिया। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 को लंबे समय तक जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, घने कोहरे के कारण वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह दुर्घटना हुई। साथ ही फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। मृतकों की पहचान राहगीर कूरान घोष और टोटो चालक सोमनाथ के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, एक बोलेरो वाहन तेज रफ्तार में राष्ट्रीय राजमार्ग-60 से होते हुए बांकुड़ा की ओर आ रहा था। उसी समय आगे टोटो लेकर सोमनाथ जा रहे थे। तभी बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टोटो को टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे पैदल चल रहे कूरान घोष को कुचल दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने अमरकानन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार बोलेरो चालक की तलाश तेज कर दी गई है।

ट्रक की टक्कर से अधेड़ की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया थाने का घेराव

रायपुर। राजधानी रायपुर के रिंग रोड स्थित गोंदवारा के पास ट्रक की टककर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के मोहल्ले गोगांव से बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पहुंचे। इसके बाद आक्रोशित परिजन और मोहल्लेवासियों ने थाने का घेराव कर आरोपित चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। पूरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना देकर थाने बुलाया था। मृतक स्थानीय निवासी होने के कारण बड़ी संख्या में परिचित और मोहल्लेवासी भी थाने पहुंचे। मृतक के साले रोहित बागड़े ने बताया कि उनके जीजा बुधवार देर शाम करीब 7 बजे काम से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। उन्होंने मांग की है कि आरोपित चालक को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। थाना प्रभारी भेखलाल चंद्राकर ने आज बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। हादसे की जांच जारी है। पुलिस ने संबंधित ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल रहा, जिसे पुलिस ने समझा कर शांत कराया।

तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप को मारी टक्कर, युवक की मौत

अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले कमरौली थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा लखनऊझ्रवाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलावा के गढ़ा मोड़ के पास उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने पिकअप वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच और आवश्यक कार्यवाही में जुटी हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कमरौली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में इलाज के दौरान सुधांशु साहू (18) पुत्र मनोज साहू, निवासी उतेलवा जनपद अमेठी की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है। कमरौली थानाध्यक्ष मुकेश पटेल ने बताया की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाते हुए हाईवे को खाली कराया। उधर मृतक युवक की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राजसमंद में पलटी कार में लगी आग, एक साल की मासूम जिंदा जली

राजसमंद। जिले में बीती रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। आमेट थाना क्षेत्र में बेकाबू कार के पलटते ही उसमें आग लग गई। हादसे में कार में सवार एक साल की मासूम बच्ची जिंदा जल गई, जबकि उसके माता-पिता, बड़ी बहन और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार रेलमगरा निवासी विकास जैन (32) अपनी पत्नी राजेश्वरी जैन, दो बेटियों धनिष्ठा (4) और प्रनिधि (1) तथा ड्राइवर कालूराम के साथ आमेट से रेलमगरा जा रहे थे। रात में आमेट थाना सर्कल में उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटते ही कार में सेकेंडों में आग भड़क उठी। आमेट थाना इंचार्ज ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि कार पलटते ही उसमें तेजी से आग लग गई, जिससे अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने साहस दिखाते हुए आग की लपटों के बीच से विकास जैन, उनकी पत्नी, बड़ी बेटी और ड्राइवर को बाहर निकाला, लेकिन एक साल की बच्ची प्रनिधि अंदर ही फंसी रह गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार कार में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिससे रेस्क्यू में करीब एक घंटा लग गया। इस दौरान कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे में घायल सभी लोगों को पहले आमेट और बाद में राजसमंद के आर.के. जिला अस्पताल रेफर किया गया। राजेश्वरी जैन के पैर में फ्रैक्चर है, जबकि विकास जैन की जीभ गंभीर रूप से कट गई है। ड्राइवर कालूराम और चार वर्षीय धनिष्ठा की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

साल के पहले दिन बढ़ी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत

- 111 रुपये महंगा हुआ 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर
- घरेलू इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने साल 2026 के पहले दिन ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर तक सीमित है, घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साल के पहले दिन ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। नई कीमत आज यानी 01 जनवरी 2026 से ही लागू हो गई है। आज की गई इस

फोटोः हि.स.

बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,691.50 रुपये हो गई है। भाव में बढ़ोतरी होने के पहले ये 1,580.50 रुपये की कीमत में उपलब्ध होता था। इसी तरह कोलकाता में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,684 रुपये से बढ़कर अब 1,795 रुपये हो गई है। मुंबई में ये अब 1,642.50 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1,531.50 रुपये थी। चेन्नई में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,739.50 रुपये से बढ़ा कर अब 1,849.50 रुपये कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में होता है। इससे पहले साल के आखिरी महीने दिसंबर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी। पिछले महीने के पहले दिन 1 दिसंबर 2025 से दिल्ली और कोलकाता में कीमत 10 रुपये, जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ती की गई थी।

घरेलू इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर (रसोई गैस) की कीमत में पिछले साल अप्रैल के बाद से अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर (रसोई गैस) की कीमत में आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदलाव हुआ था। दिल्ली में फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपये है। इसी तरह कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये, चेन्नई में 868.50 रुपये, लखनऊ में 890.50 रुपये, अहमदाबाद में 860 रुपये, हैदराबाद में 905 रुपये, वाराणसी में 916.50 रुपये और पटना में 951 रुपये है।

तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर एक फरवरी से होगा लागू

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर 01 फरवरी से लागू होंगे। तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाले नए कर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त होंगे। ये उस क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लगा, जो वर्तमान में ऐसे हानिकारक उत्पादों पर लगाया जा रहा है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, एक फरवरी, 2026 से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर 40 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा जबकि 'बीड़ी' पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा जबकि तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू व गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क संग्रह) नियम, 2026 बुधवार देर रात को अधिसूचित किए। उल्लेखनीय है कि संसद ने उन दो विधेयकों को दिसंबर में मंजूरी दी थी, जो पान मसाला बनाने पर नए स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति देते हैं। केंद्र सरकार ने इन शुल्क के एक फरवरी से लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक अलग-अलग दरों पर लगाया जाने वाला मौजूदा जीएसटी मुआवजा उपकर एक फरवरी से समाप्त हो जाएगा।

भूमि विवाद में अधेड़ महिला की पीट-पीटकर हत्या, ग्राम प्रधान पति समेत अन्य नामजद

एजेंसी (हि.स.)
अमेठी

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरे मोहम्मद नेवाज गांव में भूमि विवाद को लेकर अधेड़ महिला की पीट-पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान शिवपता (55) पत्नी स्वर्गीय छोटेलाल के रूप में हुई है। पुलिस एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ग्राम प्रधान के पति मोहम्मद तौकीर, उनके रिश्तेदार बल्लन सहित हर्षवर्धन कोरी, जयवर्धन कोरी पुत्र गोवर्धन कोरी व अन्य लोगों ने मिलकर महिला पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि मृतका और आरोपितों के बीच पिछले करीब पांच वर्षों से भूमि विवाद चल रहा था। परिजनों के अनुसार, बुधवार को दिन में शिवपता और ग्राम प्रधान के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी रंजिश में शाम के समय ग्राम प्रधान के इशारे पर कई लोगों ने रास्ते में शिवपता को घेरकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से

फोटोः हि.स.

घायल होकर मरणासन्न हो गईं। सूचना पर पहुंचे परिजन एंबुलेंस की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिरखाना लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शिवपता की मौत हो गई। मुसाफिरखाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपित ग्राम प्रधान पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बदलाव

सूरत शहर 70 लाख से अधिक आबादी वाला

देश का पहला स्लम-फ्री शहर बनने की ओर अग्रसर सूरत

एजेंसी (हि.स.)
सूरत

गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत देश का पहला ऐसा महानगर बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसकी आबादी 70 लाख से अधिक होने के बावजूद वह स्लम-फ्री (झुग्गी-मुक्त) शहर बनेगा। यह जानकारी गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री जीतुभाई वाघाणी ने मीडिया को दी है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतु वाघाणी ने बताया कि नरेन्द्र मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान शहरी क्षेत्रों को स्लम-फ्री बनाने की जो दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी पहल की थी, उसके आज सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

वर्ष 2006 में सूरत की लगभग 38 प्रतिशत आबादी झुग्गी-बस्तियों में रहती थी। झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए पिछले

फोटोः हि.स.

दो दशकों में निरंतर योजनाबद्ध प्रयास किए गए। इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि आज सूरत में झुग्गी-बस्तियों में रहने वाली आबादी घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह गई है। इससे सूरत में स्लम क्षेत्र लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रवक्ता मंत्री वाघाणी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए सूरत को गुजरात का पहला स्लम-फ्री महानगर बनाने के लिए ठोस और परिणामोन्मुख कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं।

देश में बनेगा उदाहरण

यदि सूरत यह उपलब्धि हासिल करता है तो वह देश का पहला इतना बड़ा स्लम-फ्री शहर बनेगा। हालांकि देश में पहले स्लम-फ्री शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त है, लेकिन वहां की आबादी करीब 10 लाख है। इसके मुकाबले सूरत की आबादी 70 से 80 लाख के बीच है, जिससे यह उपलब्धि आकार और जटिलता की दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अन्य शहरों के लिए भी निर्देश

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सूरत की तर्ज पर राज्य के अन्य नगरों और महानगरों को भी चरणबद्ध तरीके से स्लम-फ्री बनाने की दिशा में अभी से प्रभावी कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि पूरे गुजरात में शहरी जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। सरकार के इस प्रयास को शहरी विकास, सामाजिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम माना जा रहा है।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रारंभिक टीम घोषित

कमिंस-हेजलवुड-टिम डेविड टीम मे शामिल

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

मेलबर्न

ऑस्ट्रेलिया ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्रारंभिक (प्रोविजनल) टीम का ऐलान कर दिया है। चोट से उबर रहे पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड को टीम में शामिल किया गया है। टीम की कमान एक बार फिर मिचेल मार्श के हाथों में होगी। चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा कि कमिंस, हेजलवुड और टिम डेविड की रिकवरी सही दिशा में है और तीनों के टूर्नामेंट तक फिट होने की पूरी उम्मीद है। कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं और इस महीने के अंत में उनका स्कैन होगा, जिसके बाद अंतिम टीम पर फैसला लिया जाएगा।

बता दें की टिम डेविड को बॉक्सिंग डे पर बिग बैश लीग मैच के दौरान ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी। वहीं, जोश हेजलवुड एशेज सीरीज में एचिलीज में दर्द के कारण नहीं खेल पाए थे, जो हैमस्ट्रिंग समस्या के बाद उभरा, जबकि पैट कमिंस ने पीठ की चोट के बाद एशेज के तीसरे टेस्ट (एडिलेड) में वापसी की थी। बेली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा, टी20 टीम की हालिया सफलता को देखते हुए हमने भारत और श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुरूप संतुलित टीम चुनी है। यह प्रारंभिक टीम है, जरूरत पड़ने पर सपोर्ट पीरियड से पहले बदलाव संभव हैं। स्पिन-भारी संयोजन

ऑस्ट्रेलिया की प्रारंभिक टीम (टी20 वर्ल्ड कप)

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा।

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन-भारी संयोजन रखा है। टीम अपने ग्रुप-बी के मुकाबले कोलंबो और पल्लेकेले में खेलेगी। कैमरन ग्रीन और कूपर कॉनॉली की टीम में वापसी हुई है, जबकि जोश इंग्लिस टीम के एकमात्र विकेटकीपर हैं। मिचेल ओवेन और बेन ड्वार्शुइस को टीम में जगह नहीं मिली। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज की टीम बाद में घोषित की जाएगी।

सड़क हादसे के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए एंथनी जोशुआ, दो करीबी साथियों की मौत

लागोस। ब्रिटिश मुक्केबाज और दो बार के पूर्व हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन एंथनी जोशुआ को नाइजीरिया में हुए सड़क हादसे के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नाइजीरियाई अधिकारियों ने बुधवार देर रात इसकी पुष्टि की। यह हादसा सोमवार को लागोस के पास हुआ, जिसमें जोशुआ के दो करीबी सहयोगी और टीम सदस्य – सीना घामी और लतीफ ह्यलैट्ज अयोदेल – की मौत हो गई। घामी जोशुआ के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच थे, जबकि अयोदेल उनके ट्रेनर थे। हादसे के बाद मामूली चोटों के चलते एंथनी जोशुआ को लागोस के लैगून अस्पताल में निगरानी में रखा गया था। उनके प्रमोटर एडी हर्न की कंपनी मैचरूम बॉक्सिंग ने बताया था कि उनकी हालत स्थिर है। लागोस राज्य के सूचना आयुक्त गबेंगा ओमोटोसो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बयान जारी कर कहा कि चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के बाद जोशुआ को बुधवार दोपहर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। ओमोटोसो के अनुसार, एंथनी जोशुआ और उनकी मां बुधवार दोपहर लागोस के एक अंतिम संस्कार गृह में मौजूद थे, जहां उन्होंने अपने दोनों दिवंगत दोस्तों को अंतिम श्रद्धांजलि दी। दोनों शवों को देर शाम उनके देशों में भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। हादसे से कुछ घंटे पहले ही जोशुआ और अयोदेल ने सोशल मीडिया पर साथ में टेबल टेनिस खेलते हुए वीडियो साझा किया था। इससे पहले बुधवार को एडी हर्न ने हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, लैट्ज और सीना, शांति से आराम करें।

फुटबॉलर रॉबर्टो कार्लोस को हार्ट की समस्या, अस्पताल में भर्ती

एजेंसी (हि.स.)

रियो डी जेनेरियो

फोटोः हि.स.

ब्राजील और रियल मैड्रिड के पूर्व स्टार डिफेंडर रॉबर्टो कार्लोस को दिल से जुड़ी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्पेन के प्रतिष्ठित खेल अखबार डियारियो एएस के अनुसार, 52 वर्षीय कार्लोस को ब्राजील में छुट्टियां मनाने के दौरान मेडिकल जांच करानी पड़ी, जिसमें उनके हृदय की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, रॉबर्टो कार्लोस शुरूआत में पैर में छोटे रक्त के थक्के (ब्लड क्लॉट) की जांच कराने पहुंचे थे। हालांकि, जब पूरे शरीर का एमआरआई किया गया तो डॉक्टरों को पता चला कि उनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कर सर्जरी की गई, जिसमें हृदय में कैथेटर डाला गया।

यह प्रक्रिया करीब 40 मिनट की होनी थी, लेकिन एक जटिलता के कारण सर्जरी लगभग तीन घंटे तक चली। राहत की बात यह रही कि ऑपरेशन सफल रहा। फिलहाल रॉबर्टो कार्लोस खतरे से बाहर हैं, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें अगले 48 घंटे तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। अखबार के अनुसार, रॉबर्टो कार्लोस से संपर्क करने पर उन्होंने कहा, अब मैं ठीक हूं। रॉबर्टो कार्लोस फुटबॉल इतिहास के सबसे आक्रामक लेफ्ट बैक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने ब्राजील के लिए 125 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और रियल मैड्रिड के साथ 11 साल तक शानदार करियर बिताया। वह 1998 फीफा वर्ल्ड कप की उपविजेता और 2002 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजील टीम का हिस्सा रहे। इसके अलावा, उन्होंने 1997 और 1999 में कोपा अमेरिका जीता और रियल मैड्रिड के साथ तीन बार चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। रॉबर्टो कार्लोस अपने ऐतिहासिक बनाना फ्री किक के लिए भी दुनिया भर में मशहूर हैं। 1997 में फ्रांस के लियोन में हुए एक प्रदर्शनी टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 35 गज दूर से गेंद को अपने बाएं पैर के बाहरी हिस्से से ऐसा मोड़ा कि वह फ्रांस की तीन खिलाड़ियों की दीवार को चकमा देती हुई सीधे गोल में समा गई। यह गोल इतना असाधारण था कि वैज्ञानिकों ने भी इसका विश्लेषण किया। गेंद पहले पूरी तरह बाहर जाती हुई दिखाई दी, यहां तक कि गोल के पास खड़ा बॉल बॉय भी झुक गया, लेकिन आखिरी पल में गेंद ने अचानक दिशा बदली और नेट में चली गई। फ्रांस के गोलकीपर फैबियन बार्तेज हिल तक नहीं पाए। रॉबर्टो कार्लोस ने उस समय दावा किया था कि उन्होंने ऐसा शॉट पहले भी इंटर मिलान के लिए खेलते हुए रोमा के खिलाफ लगाया था, हालांकि 1997 जैसा करिश्मा वह दोबारा नहीं दोहरा सके।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम गुरुवार को आंशिक रूप से लागू हो गया है, जिससे एक सर्व शक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचाट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस अधिनियम को पिछले साल 18 अगस्त को अधिसूचित किया गया था और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे देश का सबसे बड़ा खेल सुधार बताया है।

जिन प्रावधानों को लागू किया जा रहा है, वे राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और शासन ढांचे से संबंधित हैं, जिनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) और क्षेत्रीय खेल संघ शामिल हैं। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, उक्त अधिनियम की धारा 1 से 3, धारा 4 की उप-धारा (1), (2) और (4), धारा 5 के उप-धारा (1) और (2), धारा 8 के उप-धारा (5), धारा 11 के उप-धारा (1), धारा 14 और 15, धारा 17 की उप-धारा (1) से (7) और (10), धारा 30 और 31, और धारा 33 से 38 के प्रावधान लागू होंगे। अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव होने के बाद सभी निकायों के लिए 15 से अधिक सदस्यों वाली कार्यकारी समितियां बनाना अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम दो खिलाड़ी (एसओएम) शामिल होंगे। अधिनियम के आंशिक रूप से लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) और राष्ट्रीय खेल पंचाट (एनएसटी) के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। एनएसबी में एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ह्ययोग्यता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से की जाएगी और जिनके पास लोक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल कानून और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। मंत्रालय ने कहा, इस अधिनियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का उद्देश्य वैधानिक खेल प्रशासन ढांचे में सुचारू बदलाव सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने उन राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को, जिनके आगामी कुछ महीनो में चुनाव होने वाले हैं, अधिनियम के पूर्ण तरह से लागू करने के लिए प्रक्रिया को दिसंबर तक स्थगित करने की अनुमति पहले ही दे दी है। इसका मतलब है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव साल के काफी अंत में होंगे। प्रस्तावित तीन सदस्यीय निकाय, एनएसबी के पास न केवल एनएसएफ को संबद्धता प्रदान करने की शक्ति होगी, बल्कि अधिनियम के पूरी तरह से लागू होने के बाद उनके वित्तीय संचालन की निगरानी करने और किसी भी कदाचार के लिए उन्हें दंडित करने की भी शक्ति होगी। सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए एनएसएफ के लिए एनएसबी से संबद्धता अनिवार्य होगी। एनएसबी के सभी सदस्यों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

क्रामनिक ने फिडे पर स्विस सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

रूस के शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रामनिक ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोदित्स्की की मौत के बाद कथित तौर पर ह्यअपुष्ट धोखाधड़ी के आरोपों के साथ खिलाड़ियों को परेशान करने के आरोप में जांच का सामना करने के बाद विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था (फिडे) के खिलाफ स्विट्जरलैंड की एक जन अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

क्रामनिक ने एक्स पर पोस्ट किया कि साथी खिलाड़ियों और फिडे ने उनके खिलाफ लगातार हमलावर तेवर अपनाए हैं जिसके कारण उन्हें कानूनी रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिडे के सीईओ एमिल सुतोवस्की ने नारोदित्स्की के खिलाफ धोखाधड़ी के क्रामनिक के आरोपों को ह्यशर्मनाक बताया था। अमेरिका के 29 वर्षीय खिलाड़ी नारोदित्स्की की मौत का सटीक पता नहीं है लेकिन उन्होंने अपने आखिरी लाइवस्ट्रीम में कहा था कि वह क्रामनिक के आरोपों के कारण बहुत मानसिक तनाव में हैं। चेक गणराज्य के ग्रैंडमास्टर डेविड नवारा ने भी कहा था कि क्रामनिक के उन पर लगाए गए ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप के कारण वह व्यथित महसूस कर रहे हैं। रूस के खिलाड़ी ने हालांकि कहा कि उन्होंने बिना किसी आधार के आरोप नहीं लगाए थे। पूर्व विश्व चैंपियन क्रामनिक ने कहा, मैंने स्विस कानून के अनुसार लुसाने की अदालत में फिडे के खिलाफ औपचारिक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। स्विस नियमों के तहत इस मामले में पहले एक अनिवार्य प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस चरण में आमतौर पर दो से तीन महीने लग जाते हैं।

मुझे लगा था कि मैं फिर कभी नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन अब गेंदबाजी करके खुश हूं: चेतन

बेंगलुरु। चेतन सकारिया को तीन साल पहले तक भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में से एक गिना जाता था लेकिन चोटिल होने के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद उन्हें लगने लगा था कि वह फिर से कभी नहीं खेल पाएंगे। सकारिया ने मौजूदा घरेलू सत्र में सौराष्ट्र की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेला जो फरवरी 2024 के बाद उनका पहला मैच है। सकारिया ने कहा, जब मुझे चोट लगी थी तो मुझे लगा था कि मैं कभी वापसी नहीं कर पाऊंगा। अब इस घरेलू सत्र में खेलकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। सौराष्ट्र के लिए गेंदबाजी करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इस तेज गेंदबाज के बाएं हाथ की कलाई में 2024 के शुरू में चोट लगी थी जिससे उबरने में उन्हें काफी समय लग गया। सकारिया ने कहा कि यह मानसिक रूप से थका देने वाला दौर था। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं दोबारा क्रिकेट खेल पाऊंगा। कुछ डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि शायद मैं दोबारा गेंद को ठीक से पकड़ भी न पाऊं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। सकारिया को निजी जीवन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में उनके पिता और छोटे भाई की मौत हो गई थी।

रियल मैड्रिड को झटकाः घुटने की चोट के कारण किलियन एम्बाप्पे बाहर

एजेंसी (हि.स.)

मैड्रिड

फोटोः हि.स.

रियल मैड्रिड के स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे बाएं घुटने में चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। स्पेनिश क्लब ने बुधवार को एक संक्षिप्त बयान जारी कर बताया कि फ्रांस के इस सुपरस्टार को घुटने में मोच (स्प्रेन) आई है, हालांकि उनकी वापसी को लेकर कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है। फ्रांस के प्रतिष्ठित खेल अखबार एलइक्विप के अनुसार, एम्बाप्पे कम से कम तीन हफ्तों तक मैदान से दूर रह सकते हैं। अखबार ने किसी आधिकारिक सूत्र का हवाला नहीं दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एम्बाप्पे पिछले कई हफ्तों से घुटने के लैटरल लिगामेंट से जुड़ी समस्या से जूझ रहे थे और बुधवार सुबह कराई गई एमआरआई जांच में ऐसी चोट (लेजन) सामने आई है, जिसके लिए इलाज और आराम जरूरी है। एम्बाप्पे इस समय शानदार फॉर्म में थे। इसी महीने की शुरूआत में उन्होंने 2025 में रियल मैड्रिड के लिए अपना 59वां गोल दागा था, जिसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक गोल करने का क्लब रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबर कर लिया। पेरिस सेंट-जर्मेन से 2024 की गर्मियों में रियल मैड्रिड से जुड़े एम्बाप्पे इस सीजन अब तक कुल 29 गोल कर चुके हैं, जिनमें से 18 गोल ला लीगा में हैं और वह लीग के शीर्ष स्कोरर भी हैं। रियल मैड्रिड का अगला मुकाबला रविवार को ला लीगा में रियल बेटिस के खिलाफ होना है, जिसमें एम्बाप्पे की गैरमौजूदगी टीम के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।

खाना-खजाना दर्पण

आसान विधि से तैयार करना है गाजर का हलवा तो ये रेसिपी है आपके काम की

नए साल की शुरूआत में हर किसी को कुछ खास और स्वादिष्ट परोसने का मन करता है। इस मौके पर गाजर का हलवा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। गाजर का हलवा न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि गाजर में विटामिन A, C, और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसे खास तौर पर सर्दी के मौसम में बनाया जाता है, और ये भारतीय मिठाई के सबसे पसंदीदा और पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। अगर आप नए साल के मौके पर अपने मेहमानों को कुछ स्वादिष्ट खिलाना चाहते हैं, तो गाजर का हलवा एक शानदार विकल्प हो सकता है। इस हलवे का मीठा और नरम स्वाद सभी को पसंद आएगा। इस हलवे को बनाना बेहद आसान है और ये बहुत कम समय में तैयार हो जाता है है। तो आइए जानते हैं गाजर का हलवा बनाने की आसान रेसिपी......

गाजर का हलवा बनाने का सामान

- गाजर (कद्दूकस की हुई) - 4 कप
- दूध - 2 कप
- घी - 2 टेबलस्पून
- खोया
- चीनी - 1 कप
- इलायची पाउडर - 1/2 टीस्पून
- काजू और बादाम - थोड़े से कटे हुए
- किशमिश - 1 टेबलस्पून (वैकल्पिक)

विधि

गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो गाजर को अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लें। इसके बाद अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालकर हल्का सा भूनें। जब ये भुन जाए तो अब इसमें दूध डालें और धीमी आंच पर पकने दें। इसे तब तक पकाएं, जब तक दूध पूरी तरह से सूख न जाए। दूध के सूखने के बाद उसमें चीनी डालें और अच्छे से मिला लें। जब तक हलवा घी छोड़ने लगे, तब तक पकने दें। चाहें तो इसी दौरान इसमें खोया डालकर पांच मिनट और पकाएं। आखिर में इलायची पाउडर और कटे हुए काजू-बादाम डालें और 2-3 मिनट तक और पकाएं। अब हलवा तैयार है। इसे गर्मागर्म सर्व करें और अपने मेहमानों को परोसें। गाजर का हलवा बनाने के लिए ताजे और मोटे गाजर का चुनाव करें। इससे हलवा का स्वाद और रंग दोनों बढ़ेंगे। हलवा को सजाने के लिए ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डाल सकते हैं, जिससे वह और भी आकर्षक लगेगा।

घर पर नई और आसान रेसिपी से बनाएं पिज्जा

नए साल का जश्न बिना स्वादिष्ट खाने के अधूरा माना जाता है। अगर आप इस खास मौके पर बाहर से ऑर्डर करने के बजाय घर पर ही कुछ स्पेशल और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो पिज्जा एक बेहतरीन विकल्प है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पिज्जा हर किसी की पहली पसंद होता है। नए साल के मौके पर घर पर बना स्पेशल पिज्जा न सिर्फ सेहतमंद होता है, बल्कि इसे आप अपने स्वाद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चाहे आप वेजिटेरियन हों या चीज लवर, घर पर बना पिज्जा हर तरह से परफेक्ट रहता है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा समय या महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। अगर आप भी नए साल के मौके पर अपने परिवार और दोस्तों को कुछ खास खिलाना चाहते हैं, तो ये स्पेशल पिज्जा रेसिपी जरूर ट्राई करें।

डिटेल रेसिपी

- पिज्जा बेस
- पिज्जा सॉस
- मोजरेला चीज
- शिमला मिर्च
- प्याज
- टमाटर
- स्वीट कॉर्न
- ऑलिव्स
- ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स
- नमक स्वादानुसार

विधि

सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। पिज्जा बनाने से पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्री-हीट कर लें, ताकि पिज्जा सही तरीके से बेक हो सके। अब पिज्जा बेस लें और उस पर पिज्जा सॉस को चम्मच या ब्रश की मदद से चारों तरफ बराबर फैलाएं। ध्यान रखें कि सॉस ज्यादा मोटी परत में न हो, इससे पिज्जा सॉफ्ट हो सकता है। इसके बाद कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज की एक हल्की परत डालें, जिससे टॉपिंग अच्छे से चिपक जाए। अब तैयार की गई सब्जियां जैसे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, स्वीट कॉर्न और ऑलिव्स को बेस पर अच्छी तरह फैलाएं। सब्जियों के ऊपर स्वादानुसार नमक, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़कें। चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसके बाद ऊपर से चीज की एक और लेयर डालें ताकि पिज्जा ज्यादा चीजी और टेस्टी बने। अब पिज्जा ट्रे को ओवन में रखें और 10 से 15 मिनट तक बेक करें। जब चीज पूरी तरह मेल्ट होकर हल्का सुनहरा रंग लेने लगे और पिज्जा बेस क्रिस्पी हो जाए, तो पिज्जा निकाल लें।

बिना तंदूर के ऐसे बनाएं पनीर टिक्का, जिसे मेहमान खूब चाव से खाएंगे

नए साल की पार्टी को खास और यादगार बनाने के लिए लोग अक्सर कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाने की तलाश में रहते हैं। अगर आप इस बार घर पर पार्टी होस्ट कर रहे हैं और मेहमानों को कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं, तो पनीर टिक्का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। ये न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि देखने में भी काफी आकर्षक लगता है।

खास बात ये है कि पनीर टिक्का बनाने के लिए आपको तंदूर या ओवन की जरूरत नहीं है, इसे आप आसानी से तवे पर भी बना सकते हैं। सही मसालों और दही के साथ मैरिनेट किया गया पनीर टिक्का पार्टी स्नैक्स के तौर पर सभी को पसंद आता है। ये रेसिपी झटपट बन जाती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की फेवरेट होती है। आइए जानते हैं तवे पर बनने वाले खास पनीर टिक्का की आसान और सही विधि।

सामग्री

- 250 ग्राम ताजा पनीर (चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)
- ½ कप गाढ़ा दही
- 1 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
- 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- ½ चम्मच हल्दी पाउडर
- 1 चम्मच धनिया पाउडर
- ½ चम्मच गरम मसाला
- 1 चम्मच चाट मसाला
- 1 चम्मच नींबू का रस
- चम्मच सरसों का तेल
- नमक स्वादानुसार
- शिमला मिर्च
- प्याज के टुकड़े

तवे पर पनीर टिक्का बनाने की विधि

सबसे पहले 250 ग्राम पनीर को चौकोर टुकड़ों में काट लें। अब एक कटोरी में गाढ़ा दही लें और उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नींबू का रस और नमक मिलाएं। इस मिश्रण में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें पनीर के टुकड़े डालकर हल्के हाथों से मिलाएं और कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। इसके बाद तवे को गरम करें, थोड़ा तेल लगाएं और पनीर टिक्के को धीमी आंच पर चारों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। तैयार टिक्के को हरी चटनी और सलाद के साथ परोसें।

वर्तमान सरकार ने सेवा भाव के साथ सुशासन के माध्यम से आमजन के जीवन को बनाया सुगम, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिला योजनाओं का लाभ: सैनी

भूपेंद्र शर्मा

पंचकूला

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार सेवा भाव के साथ सुशासन के माध्यम से आमजन के जीवन को सुगम बनाने और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पंहुचाने का कार्य कर रही है। उनका विजन हरियाणा को सुशासन के क्षेत्र में देश का उदहारण बनाना है और इस दिशा में सुशासन सहयोगी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट सेक्टर-3 में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी 2.0 के अंतर्गत नवनियुक्त सुशासन सहयोगियों की आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों को स्टेशन आवंटित किए। सभी सुशासन सहयोगी कल 2 जनवरी से अपने-अपने संबंधित जिलों में कार्यभार संभालेंगे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, उप प्रधान सचिव और सीएमजीजीए कार्यक्रम के परियोजना निदेशक श्यशपाल सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राकेश संधु और सभी जिलों के उपायुक्त भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित नवनियुक्त सीएमजीजीएज और सभी जिला उपायुक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरे लिए सुशासन का अर्थ है- पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशन। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह केवल नारा नहीं है। यह हमारा प्रशासनिक संकल्प है।इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें मजबूत ढाँचा बनाना होगा। वह ढांचा बनता है बेसिक चीजों से, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन, और सही गवर्नेंस से।

- मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सुशासन सहयोगियों को दिया सुशासन का मंत्र
- मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए सुशासन का अर्थ है पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशन
- राज्य सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा और सुशासन पर विशेष फोकस: मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुशासन वास्तव में घटित तब होता है, जब किसान को, मजदूर को समय पर सरकारी नीतियों का लाभ मिले। वंचित वर्गों को उनके हक मिलें। जब नागरिकों को स्वास्थ्य केंद्र में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले और जब बच्चों को विद्यालय में वास्तविक अर्थों में अच्छी शिक्षा मिले। सुशासन का यही अर्थ है कि बनी हुई योजनाओं और नीतियों का धरातल पर असर दिखाई दे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य किया है। आज लोगों को घर बैठे विभिन्न कल्याणारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उन्हें अपने कार्यो के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लोगों का विश्वास सरकार में मजबूत हुआ है और यहीं सुशासन की पहचान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य होते हुए भी अनेक क्षेत्रों में देश में अग्रणीय है। यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को देश का ग्रोथ इंजन कहा है। प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने में हरियाणा की अहम भूमिका रहेगी।

कहा कि सुशासन सहयोगी उपायुक्तों के सबसे उपयोगी सहयोगी हैं और ये युवा विभिन्न विभागों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सुशासन सहयोगियों का प्रदेश के विकास में पूरा सहयोग लें। ये उनके साथ मिलकर प्रशासन की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे।

उन्होंने उपायुक्तों और सुशासन सहयोगियों से आान किया कि वे मिलकर राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा और सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए विकसित हरियाणा-विकसित भारत के विजन का साकार करने में अमूल्य योगदान दें। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यह केवल साफ सफाई का मुद्दा नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और नागरिकों की गरिमा से जुडा हुआ है।

उन्होंने सुशाासन सहयोगियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए जन जन के कल्याण के लिए दिन रात काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सुशासन सहयोगियों के रूप में तीसरा इंजन भी है, जो जमीनी सच्चाई देखते हैं, नागरिकों की वास्तविक समस्याएं सुनते हैं और समाधान की दिशा में प्रशासन को और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव और सीएमजीजीए कार्यक्रम के परियोजना निदेशक श्री यशपाल ने सीएमजीजीए कार्यक्रम के मॉड्यूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी।ग्लोबल विलेज फाउंडेशन के निदेशक सुमित कुमार ने सीएमजीजीए कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि नवनियुक्त सीएमजीजीए को प्रशासनिक सुधार, नीति निर्माण सहित विभिन्न विषयों पर 140 घंटो से अधिक का प्रशिक्षण दिया गया है और 68 से उपर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुलभूषण गोयल के 5 वर्ष के विकास कार्यों की पुस्तक का विमोचन

सिटी दर्पण संवाददाता

पंचकूला

पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल द्वारा पिछले 5 वर्ष में करवाए गए विकास कार्यों की पुस्तक का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने खुशी व्यक्त की कि पिछले 5 साल में कुलभूषण गोयल ने 400 करोड़ रुपये के काम करवाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। नायब सैनी ने कहा कि इन विकास कार्यों का आगामी नगर निगम चुनावों में भी भाजपा को लाभ मिलेगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला भाजपा जिला प्रधान अजय मित्तल, विभिन्न वार्डों के भाजपा पार्षद भी उपस्थित रहे। कुलभूषण गोयल ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले पांच वर्षों में पंचकूला शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की शुरूआत की गई, वहीं शहर को आकर्षक रूप देने के लिए सभी एंट्री प्वाइंट और चौकों पर रंग-बिरंगी लाइटें लगवाई गईं। दिव्य नगर योजना के तहत 12 करोड़ रुपये की लागत से एलईडी लाइट ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए सप्ताह में छह दिन अलग-अलग स्थानों पर किसान मंडियां शुरू की गईं। शहर के पार्कों में ईपीडीएम ट्रैक, खेल सुविधाएं और स्टेडियम विकसित किए गए। शहर में सामुदायिक केंद्रों, बैंक्वेट हॉल, वेंडिंग जोन, रेलवे अंडरब्रिज-ओवरब्रिज, पार्कों के नवीनीकरण, सड़कों की रिकार्पेटिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, एनएमटी ट्रैक, डिजिटल बोर्ड, मोबाइल टॉयलेट्स और कूड़ेदानों की व्यवस्था की गई। साथ ही, आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या के समाधान, डेंगू नियंत्रण के लिए फॉगिंग तथा ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने के कार्य भी निरंतर जारी रहे। कुलभूषण गोयल ने कहा कि इन विकास कार्यों का उद्देश्य पंचकूला को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाना है, ताकि शहरवासियों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। गोयल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

नए साल का मील का पत्थर: पीजीआई ने संगरूर सैटेलाइट सेंटर में हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

नए साल पर एक और मील का पत्थर हासिल करते हुए, पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई), चंडीगढ़ ने 1 जनवरी 2026 से पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, संगरूर में अपना हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है, जो इंस्टिट्यूट की डिजिटल हेल्थ यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, पीजीआई के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल ने कहा, संगरूर में सफल रोलआउट हॉस्पिटल सेवाओं के व्यापक डिजिटलीकरण के प्रति पीजीआई के केंद्रित दृष्टिकोण को दशार्ता है। यह सिस्टम दक्षता, पारदर्शिता और मरीजों की सुविधा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसी डिजिटल फ्रेमवर्क को पीजीआई चंडीगढ़ में और मजबूत किया जाएगा और लागू किया

जाएगा ताकि सभी पीजीआई सुविधाओं में एक समान, निर्बाध और मरीज-केंद्रित सेवा प्रदान की जा सके। पहले चरण में, रोगी पंजीकरण, बिलिंग, और प्रवेश-छुट्टी-स्थानांतरण सहित आवश्यक मॉड्यूल चालू कर दिए गए हैं और वर्तमान में नियमित हॉस्पिटल कार्यों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। डॉक्टर डेस्क, प्रयोगशाला सेवाएं, और स्टोर/इन्वेंटरी प्रबंधन जैसे अतिरिक्त मॉड्यूल प्रशिक्षण और ट्रायल रन के उन्नत चरणों में हैं और एकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो को पूरा करने के लिए जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इस पहल के बारे में और जानकारी देते हुए, पीजीआई के उप निदेशक (प्रशासन) श्री पंकज राय ने कहा, 'संगरूर में 1 जनवरी 2026 से चालू करने के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय की गई थी, और सभी संबंधित टीमों के करीबी समन्वय और लगातार प्रयासों से लक्ष्य हासिल किया गया।' इन्फॉर्मेशन सिस्टम को पीजीआई के व्यापक डिजिटल परिवर्तन रोडमैप के हिस्से के रूप में नोएडा द्वारा विकसित किया गया है। संगरूर सैटेलाइट सेंटर, जो 350 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है, इस मजबूत सिस्टम को अपनाने वालों में से एक है, जिसका उद्देश्य हॉस्पिटल के संचालन को सुव्यवस्थित करना, रीयल-टाइम डेटा तक पहुंच में सुधार करना और रोगी देखभाल की समग्र गुणवत्ता को मजबूत करना है। संगरूर में सफल शुरूआत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने और कुशल, पारदर्शी और रोगी-केंद्रित सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति पीजीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

मुख्य सचिव ने नववर्ष की बधाई दी एवं प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर दिया जोर

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

यू.टी. चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, श्री एच. राजेश प्रसाद ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और सभी के सुखी, स्वस्थ एवं समृद्ध वर्ष की कामना की।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से मध्यम एवं निचले स्तर के कर्मचारियों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रशासन की विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों को सक्रिय रूप से जोड़ें, जिससे प्रशासन अधिक उत्तरदायी, नागरिक-केंद्रित एवं प्रभावशाली बन सके। उन्होंने सामूहिक प्रयास एवं टीमवर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यही तत्व सार्वजनिक सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने और चंडीगढ़ की एक सुशासित शहर के रूप में पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य अवसंरचना को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे शहर के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ निरंतर उपलब्ध कराई जा सकें।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवा प्रदायगी के अग्रिम स्तर पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मध्यम स्तर के अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की निकटता से निगरानी एवं समीक्षा करें, ताकि उत्तरदायित्व, कार्यकुशलता और सार्वजनिक शिकायतों के समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में प्रक्रियागत सुधार लागू करने की भी आवश्यकता बताई, जिससे कार्यप्रवाह सुव्यवस्थित हो, दक्षता में वृद्धि हो और सेवा प्रदायगी गुणवत्ता में सुधार आए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कर्मचारी प्रेरित होकर, अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ कार्य करें और प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर टीम भावना के साथ आगे बढ़ें।

अपने संबोधन का समापन करते हुए मुख्य सचिव ने कहा, आइए हम सब मिलकर चंडीगढ़ को हर क्षेत्र में प्रथम बनाएं – सुशासन, सार्वजनिक सेवा एवं नागरिकों के जीवन स्तर में नए मापदंड स्थापित करें।

बैठक में श्री मांडिप सिंह ब्रार, गृह सचिव; श्री सागरप्रीत हूडा, पुलिस महानिदेशक; श्री दिप्रवा लाकड़ा, वित्त सचिव सहित अन्य सचिवगण एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

नए वर्ष के उपलक्ष्य में सीपीए द्वारा लंगर सेवा आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

नए वर्ष के प्रथम दिन चण्डीगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन (सीपीए) द्वारा एक सेवा भाव से परिपूर्ण लंगर सेवा का आयोजन संस्था के चेयरमैन जेपी गरचा, प्रेसिडेंट सरोज चौहान एवं महासचिव सुनील भट्ट के नेतृत्व में सेक्टर 22-बी में पिकाडिली होटल के नजदीक आयोजित किया गया जिसमें सीपीए के चीफ पैटर्न एवं वरिष्ठ सदस्य बेदी तथा पूर्व चेयरमैन नरेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और लंगर सेवा में हाथ बंटाकर अपना योगदान दिया।

इस अवसर पर मुख्य रूप से चण्डीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) के प्रधान संजीव चड्ढा व एरिया पार्षद दमनप्रीत सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने भी लंगर वितरित कर सीपीए का उत्साहवर्धन किया तथा इस सराहनीय सेवा कार्य के लिए भूरी-भूरी प्रशंसा की।

लंगर सेवा के अंतर्गत श्रद्धालुओं को चाय एवं पकोड़ों का प्रसाद वितरित किया गया। लंगर में लगभग 5,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान सीपीए के सभी सदस्यों एवं ट्राईसिटी के फोटोग्राफर साथियों ने बढ़-चढ़कर सेवा प्रदान की।

संक्षिप्त-समाचार

भाजपा, कांग्रेस व आप नेताओं ने जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी कार्यक्रम में लंगर बरताया

चंडीगढ़। जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी, चण्डीगढ़ की ओर से नए साल के पहले दिन सेक्टर 22 में चाय और ब्रेड पकोड़े का लंगर लगाया गया जिसमें शहर की तीनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने लंगर बरतने की सेवा की। संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सुनील शर्मा ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष एचएस लक्की व आप पार्टी के नेता एवं एरिया पार्षद दमनप्रीत बादल ने लंगर सेवा में बढ़-चढ़ कर सेवा कार्य में हाथ बंटाया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने लंगर का आनंद लिया। इस मौके पर जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अमित सिंगला और प्रेसिडेंट अश्विनी सिंगल भी उपस्थित रहे।

जीवन बीमा सेक्टर ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल रहा: सुमित राय

चंडीगढ़। जीवन बीमा यह उद्योग हर साल लगातार आगे बढ़ रहा है। सुमित राय, एमडी और सीईओ, एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के अनुसार जैसे-जैसे भारत की जनसंख्या में बदलाव आ रहा है, जीवन बीमा सेक्टर भी ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल रहा है। ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उत्पाद, सेवाएं और पीछे के कामकाज में कई नए और बेहतर तरीके अपनाए गए हैं। उत्पादों में अब ज्यादा लचीलापन और हर व्यक्ति के अनुसार बदलाव पर ध्यान दिया जा रहा है। केवल जीवन बीमा तक नहीं, बल्कि बड़े जीवन घटनाओं और धन बनाने की जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। उद्योग ने अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाया है ताकि ग्राहक को आसान, तेज और सरल सेवा मिल सके। 2026 में यह सुधार और इन्नोवेशन जारी रहेगा, क्योंकि उद्योग अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतें पूरा करेगा। टेक्नोलॉजी खासकर बीमा के काम करने के तरीके को बदल रही है। एआई अब सिर्फ. टेस्ट में नहीं, बल्कि असली काम में और बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रही है। बीमा कंपनियां एआई से ज्यादा लाभ कमाने और जोखिम संभालने का काम कर रही हैं। अगले 2-3 साल में सबसे बड़ा बदलाव बीमा बेचने के तरीके में आएगा, जो अब तक आमने-सामने मिलने पर निर्भर था। एआई अब हर ग्राहक बातचीत से उपयोगी जानकारी निकालने में मदद करती है, जिससे बीमा कंपनियां हर ग्राहक के लिए सेवाओं और उत्पादों को खास बना सकती हैं, बातचीत को बेहतर कर सकती हैं और हर स्तर पर सेवा सुधार सकती हैं। धीरे-धीरे, यह छोटे समूहों या अकेले व्यक्तियों के लिए भी पूरी तरह से कस्टम समाधान देने में मदद करेगा, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां बीमा हर व्यक्ति के लिए अनुकूल होगा। यह व्यक्तिगत सेवा ग्राहक की निष्ठा बढ़ाती है, उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत करती है और बीमा बेचने के तरीके बदल देती है।

एम3एम फाउंडेशन ने वर्ष 2025 को देशव्यापी मापनीय सामाजिक प्रभाव के साथ किया

चंडीगढ़/गुरुग्राम। एम3एम फाउंडेशन ने पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और खेल जैसे क्षेत्रों में एकीकृत हस्तक्षेपों के माध्यम से 22 राज्यों, 90 जिलों और 1,349 गांवों में 4.9 मिलियन लोगों तक अपनी सामाजिक पहुंच का विस्तार करके साल का समापन किया। 50 से ज्यादा संगठनों के साथ साझेदारी में लागू किए गए फाउंडेशन का काम ग्रामीण, शहरी और वंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने, समानता और दीर्घकालिक सामुदायिक लचीलेपन पर केंद्रित है। इस साल, फाउंडेशन ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिणाम दिए, जिसमें 31 लाख से ज्यादा लोगों को पर्यावरणीय लाभ, 7.8 लाख बच्चों को शैक्षिक सहायता, 6.2 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और 2.5 लाख लोगों के लिए आजीविका में सुधार शामिल है। इन हस्तक्षेपों ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्राकृतिक खेती, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा वितरण, पोषण, कौशल विकास, उद्यमिता और समुदाय-नेतृत्व वाली सस्टेनेबिलिटी पहलों में महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा किया। 2025 में, केंद्रित हस्तक्षेपों ने प्रभाव को और गहरा किया। पर्यावरणीय कार्रवाई के परिणामस्वरूप 30 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल भंडारण का निर्माण हुआ, 52,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए, और 2,500 किसानों को प्राकृतिक खेती में सहायता मिली, जिसमें 60 प्रतिशत महिला लाभार्थी थीं, जबकि 25,000 ग्रामीणों को मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व पहलों से लाभ हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, 1,736 प्रवासी बच्चों को सहायता दी गई, देश भर में 828 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, और 20,000 से ज्यादा छात्रों को डिजिटल कक्षाओं से लाभ हुआ। खेल पहलों ने 104 खिलाड़ियों को सहायता दी, जिससे 310 से ज्यादा पदक मिले, जिसमें 71 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शामिल हैं।

बबला की अगुआई में जरूरतमंद महिला घरेलू कामगारों को कंबल वितरित किए

चंडीगढ़। नवगठित वेलफेयर कमेटी (डब्ल्यूसी), सेक्टर 27-डी के सदस्यों ने नव वर्ष के शुभारम्भ के अवसर पर शीत लहर के प्रकोप के बीच सामूहिक रूप से सेक्टर 27-डी की जरूरतमंद महिला घरेलू कामगारों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर भाजपा के स्थानीय उपाध्यक्ष देविंदर बबला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सुभाष पलटा, अध्यक्ष, अमरदीप सहगल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लवलीन कौर, उपाध्यक्ष, परवीन मित्तल, महासचिव तथा नवगठित वेलफेयर कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी 5 जिलावासियों की समस्याएं

उपायुक्त ने गांव भोज बालंद की धनवंती की रास्ता देने की मांग पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को मोके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता

पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज हरियाणा सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में जिला के 5 लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर संबंधित विभाग को समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने शिविर में गांव भोज बालंद की धनवंती की रास्ता देने की मांग पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को मोके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आई शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर बिना विलम्ब किए समाधान करें ताकि जिलावासियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके व उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर का आयोजन मुख्यमंत्री श्री नायाब सैनी के निदेर्शानुसार हर कार्यदिवस के दिन सोमवार व वीरवार को प्रात 10 बजे से 12 बजे तक किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं समाधान शिविर से जुडते हैं व लोगों की समस्याओं पर किए गए समाधान की स्वयं मोनिटरिंग करते है। इसलिए समस्याओं के समाधान में अधिकारी किसी प्रकार की कोताही न बरतें। इस अवसर पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, एचएसवीपी, पीएमडीए, पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, नगर निगम ओर अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलों की बुआई करने पर कृषि विभाग ने दिया बल

पंचकूला। हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे कपास, मक्का, अरहर, मुंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, तिल, अरण्डी, मुंगफली, फल व सब्जियां, खरीफ प्याज, खरीफ चारा व कृषि वानिकी (सफेदा व पोप्लर) द्वारा विविधिकरण करने के लिए जिला में 1500 एकड का लक्ष्य दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि किसान अपने पिछले वर्ष बोये गए धान के क्षेत्र को उपरलिखित वैकल्पिक फसलों में बदल सकता है। वर्ष 2025 से पहले किसान द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापन उपरांत किसान को 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तिय सहायता प्रदान की जाती थी जोकि इस वितीय वर्ष से 8000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है और डी0बी0टी0 के तहत किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत किसान द्वारा पिछले वर्ष बोई गई धान के खेत को खरीफ 2025 में खाली रखने पर भी वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उपरलिखित वैकल्पिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उक्त फसलों की 100 प्रतिशत खरीद हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उन्होंने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा कि भूमिगत जल के संरक्षण हेतू धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें बोने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं व अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि/बागवानी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।